घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 102- बुधवार 11- फरवरी 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश,118 सांसदों के हस्ताक्षर

अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला होने तक सदन में नहीं आएंगे लोकसभा स्पीकर बिरला

नई दिल्ली,10 फरवरी 2026। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की औपचारिक पहल कर दी है। पार्टी ने इस संबंध में लोकसभा महासचिव को नोटिस सौंपा है, जिस पर कुल 118 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। यह प्रस्ताव लोकसभा के नियम 94(सी) के तहत दाखिल किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि नियमों के अनुरूप इसकी जांच के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब संसद के मौजूदा सत्र में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच टकराव चरम पर है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने का अवसर नहीं दिया गया। इसके अलावा,कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ कथित रूप से अनुचित व्यवहार का मुद्दा भी विपक्ष द्वारा उठाया गया है। विपक्ष का कहना है कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों को खुलकर बोलने की छूट दी जा रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ओम बिरला अब लोकसभा नहीं जाएंगे।अविश्वास प्रस्ताव के गिरने के बाद ही वह स्पीकर की चेयर संभालेंगे। एजेंसी के मुताबिक विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में 9 मार्च को चर्चा हो सकती है।

रिजिजू बोले...कोई प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे अविश्वास से...

इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसे अविश्वास प्रस्ताव से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है,क्योंकि विपक्ष के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने सदन में अनुशासनहीनता दिखाई और स्पीकर के पद की मर्यादा का उल्लंघन किया। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्पीकर से किसी विशेष कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं।

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी बोले...सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है...

टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सरकारी कंपनियों को ये सरकार बेच रही है। पीएम कहते हैं कि ना खाउंगा ना खाने दूंगा और वही पार्टी खुद वॉशिंग मशीन बन गई है। ये केवल अपने दोस्तों को फायद पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी क्षेत्र में काम नहीं कर पा रही है। ये खर्च ही नहीं कर रहे हैं। सरकार की कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं रह गई है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने संसद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि युवाओं और महिलाओं को लेकर सरकार की नियत में ही खोट है। ये सरकार लोगों के बीच हेट बढ़ा रही है। ये अपने भाषण में लोगों को भड़काते हैं।

अखिलेश यादव बोले...नए लेबर कोड लेबर के ही पक्ष में नहीं है

अखिलेश यादव ने कहा ... कि इस डील और ढील के बाद रुपये का क्या हाल होगा सरकार बताए। यादव ने कहा कि सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। ये लेबरकोड लाए जो लेबर के पक्ष में ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अपना आवंटित बजट ही खर्च नहीं कर रही है। पीएम ने गोद लिए गांव को अनाथ छोड़ दिया। सरकार मेरे सवालों का जवाब दे। सभी क्षेत्र की रैंकिंग में हम काफी नीचे आ गए हैं। 2047 तक विकसित भारत तो नहीं बनेगा लेकिन गरीबों के साथ बहुत अन्याय होगा।

विपक्षी दलों की हुई अहम बैठक : इससे पहले मंगलवार सुबह संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में विपक्षी दलों की अहम बैठक हुई थी। बैठक में तृणमूल कांग्रेस,वाम दल,डीएमके, समाजवादी पार्टी,राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) सहित कई दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई।

सांसद पप्पू यादव को पटना कोर्ट से जमानत

31 साल पुराने मामले में हुई थी गिरफ्तारी

पटना,10 फरवरी 2026। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को पटना के कोर्ट से जमानत मिल गई। सिविल कोर्ट के एसीजेएम-1 की कोर्ट में उनकी पेशी हुई थी। पटना सिविल कोर्ट में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। कोर्ट के अंदर आने-जाने वाले हर व्यक्ति की बारिकी से जांच की जा रही है। अभी कल ही पटना सिविल कोर्ट बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। जिसे लेकर पटना सिविल कोर्ट में गहमागहमी का माहौल है। कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है।

तीन दशक पुराने केस में हुई थी गिरफ्तारी

दरअसल, करीब तीन दशक पुराने एक मामले में गिरफ्तारी के बाद से सांसद पप्पू यादव पटना के बेऊर जेल में कैद थे। पप्पू यादव की जमानत याचिका पर कोर्ट में सोमवार को ही सुनवाई होनी थी। लेकिन अचानक पटना सिविल कोर्ट में बम रखने जाने की सूचना ईमेल से आई, जिसके बाद वहां अफरातफरी का माहौल हो गया। पटना पुलिस इसकी जांच-पड़ताल में जुट गई। कोर्ट परिसर को खाली करवा कर चेकिंग की गई थी। इससे न्यायिक कामकाज भी बाधित हुए। जिसके चलते पप्पू यादव की याचिका पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। जेल से बाहर आने के लिए सांसद पप्पू यादव का इंतजार बढ़ गया था। मगर, आज का उनके लिए खुशिया लेकर आया।

पप्पू यादव की क्यों हुई थी गिरफ्तारी?

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को 6 फरवरी 2026 को पटना के 31 साल पुराने धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये मामला साल 1995 का है, जो पटना के गर्दनीबाग थाने में दर्ज हुआ था।

शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने उनका मकान व्यक्तिगत उपयोग के नाम पर किराए पर लिया था,लेकिन बाद में उसका इस्तेमाल धोखे से सांसद के कार्यालय के रूप में किया जाने लगा। इस मामले में धारा 467 (दस्तावेजों की जालसाजी) समेत अन्य गंभीर धाराएं लगी थीं।

किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' पर जनरल नरवणे की पहली प्रतिक्रिया,पेंगुइन के बयान को सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

नई दिल्ली,10 फरवरी 2026। पूर्व थलसेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपनी पुस्तक फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर पहली बार सार्वजनिक प्रतिक्रिया दी है। जनरल नरवणे ने इस संबंध में पेंगुइन इंडिया की ओर से जारी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। प्रकाशन ने कहा था कि कंपनी द्वारा पुस्तक की कोई भी प्रति ''मुद्रित या डिजिटल रूप में'' प्रकाशित, वितरित,बेची या किसी अन्य तरीके से जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई है। अब पेंगुइन इंडिया के ट्वीट पर रिट्वीट करते हुए जनरल एमएम नरवणे ने एक्स पर लिखा कि यह किताब की स्थिति है। इसी बीच प्रकाशन की ओर से एक अन्य बयान भी जारी किया गया है। जिसमें प्रकाशक ने कहा है कि किसी किताब या उसके प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होने की घोषणा को पब्लिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। इसके साथ पब्लिकेशन हाउस ने कहा है कि प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध किताब और पब्लिश हुई किताब एक ही बात नहीं हैं। 'पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया' (पीआरएचआई) ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के संस्मरण 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' की अनधिकृत प्रतियां उपलब्ध होने की खबरों के बीच कहा है कि इसके प्रकाशन का अधिकार केवल उसके पास है और यह पुस्तक अब तक प्रकाशित नहीं हुई है। इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक के सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी।

असम सीएम हिमंत सरमा ने गोगोई पर ठोका 500 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा,आरोपों पर किया पलटवार

नई दिल्ली,10 फरवरी 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा और दुर्भावनापूर्ण बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आरोप उनकी छवि खराब करने के इरादे से लगाए गए हैं। इन आरोपों के खिलाफ मुख्यमंत्री सरमा ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई और दो अन्य लोगों के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि (डिफेमेशन) का केस दर्ज कराया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाए, जिससे उनकी व्यक्तिगत और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने साफ कहा कि वह इस मामले में कानूनी रास्ते से जवाब देंगे। सरमा ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाना गलत है। इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। गौरव गोगोई ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर आरोप लगाया कि 12,000 बीघा जमीन का मुद्दा सामने आने और लोगों के नए बोर असम की मांग को लेकर उनके खिलाफ पुराने राष्ट्रविरोधी आरोपों को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि समय परिवर्तन यात्रा से कथित 12,000 बीघा जमीन हड़पने का मामला उजागर हो रहा है। गोगोई ने पत्रकारों से कहा कि पहले मैंने भी कहा था कि यह असफल होगा; यह असफल नहीं, बल्कि बेहद असफल है।

चुनाव से पहले युवाओं के खाते में 15 सौ रुपये देगी ममता सरकार

कोलकाता,10 फरवरी 2026। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंतरिम बजट में घोषित 'युवसाथी' योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार यह योजना अब एक अप्रैल से लागू करेगी। इसके तहत राज्य के 21 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार युवाओं को हर महीने 15 सौ रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले यह योजना 15 अगस्त से शुरू करने का निर्णय लिया गया था लेकिन नया आर्थिक वर्ष एक अप्रैल से शुरू होता है इसलिए उसी दिन से योजना लागू करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस योजना का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और जो वर्तमान में बेरोजगार हैं। यह भत्ता अधिकतम पांच वर्षों तक दिया जाएगा।

बाबरी ढांचा कयामत के दिन तक नहीं बनेगा...जो कानून तोड़ेगा उसे जहन्नुम मिलेगा,कायदे से रहना सीख लो : योगी

बाराबंकी,10 फरवरी 2026। कयामत की रात कभी नहीं आएगी, इसलिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कभी संभव नहीं है। जो लोग कयामत के दिन का सपना देख रहे हैं, वे ऐसे ही सड़-गल जाएंगे। ऐसे लोगों से कहना चाहेंगे कि कयामत के दिन के लिए मत जियो। हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, क्योंकि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जो कानून तोड़ेगा,वो सीधे जहन्नुम में जाएगा। यह बात सीएम योगी ने मंगलवार को बाराबंकी में कही। उन्होंने कहा...ये डबल इंजन की सरकार है। हम लोगों ने कहा था ना,रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बन गया न मंदिर। कोई संदेह है। राम को भूल जाते हैं,इसलिए भगवान राम भी उनको भूल चुके हैं। अब उनकी नैया कभी पार नहीं होगी। उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ना। रामद्रोहियों के लिए अब कोई जगह नहीं। जो रामभक्तों पर गोली चला रहे थे,अब इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं। राम सबके हैं,इसमें भेद नहीं। कुछ अवसरवादी राम को भूल जाते हैं।

मोदीजी आए तो गरीबों को घर मिले

योगी ने कहा ... पहले गरीबों के घर नहीं बन पाए। मोदीजी आए,तो यूपी के 60 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिले। पहले गांवों में बिजली नहीं थी, सड़कों पर गंदगी थी। अब घर-घर शौचालय बन गए। साफ पानी मुहैया कराया जा रहा है। पहले बिजली नहीं मिलती थी। कुछ चुनिंदा जिलों को ही बिजली मिलती थी। अब सभी 75 जिलों को बिजली मिल रही। पहले की सरकारों में शौचालय नहीं थे। लोगों को मुंह बंद करके खेतों में जाना पड़ता था। आज हर घर में शौचालय है। अब बहन-बेटियों को बाहर नहीं पड़ता। बेटियों के जन्म से लेकर शादी का खर्च भी सरकार कर रही है। ये समाज की जिम्मेदारी है।

2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था

योगी बाराबंकी में श्री हनुमत विराट महायज्ञ एवं श्रीरामार्चा पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यज्ञ मंडप में आहुति दी। इस दौरान संत बलराम दास ने मखाने और लावा की माला पहनाकर योगी का स्वागत किया। इसके बाद योगी ने कहा...हम सब भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें। 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था। पहले गरीबों की जमीन पर कब्जा हो जाता था। सरकार बदलते ही सारी अराजकता गायब हो गई। हमारी सरकार में सब सुरक्षित हैं। योगी ने कहा...बेटी सुरक्षित होगी, तो समाज अपने आप सुरक्षा का एहसास करेगा। व्यापारी सुरक्षित होगा, तो तरक्की होगी। पहले वेतन देने का पैसा नहीं होता था। आज सभी को वेतन समय पर मिल रहा। सरकार करोड़ों लोगों को पेंशन दे रही है। आज प्रदेश तरक्की कर रहा है।

500 साल में मंदिर नहीं बना

सीएम ने कहा...500 साल में कई राजा-महाराजा आए। 1947 में देश आजाद हुआ। सरकारें बनती रहीं। लेकिन,किसी मन में ये बात नहीं आई कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। मंदिर भाजपा की सरकार में बना। आज वहां लाखों भक्त दर्शन करने जा रहे।

हमने केडी सिंह बाबू की हवेली बिकने नहीं दी

योगी ने कहा...बाराबंकी भगवान विष्णु के वराह अवतार की भूमि है। यहीं लोधेश्वर महादेव का पवित्र धाम है। इसी धरती पर हॉकी के महान खिलाड़ी और पद्म सम्मान से सम्मानित बाबू केडी सिंह का जन्म हुआ था। उनकी हवेली बिकने वाली थी। लेकिन, सरकार ने उसे बिकने नहीं दिया। अपने खर्चे से वहां भविष्य स्मारक बनवाया जा रहा है। जिससे जनपद का नौजवान उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ सके। योगी ने कहा... बाराबंकी के प्रगतिशील किसानों ने आधुनिक खेती के जरिए जिले को नई पहचान दी है।

असम में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश...2.43 लाख नाम हटे

राज्य में अब 2.49 करोड़ वोटर्स,यहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं

गुवाहटी,10 फरवरी 2026। चुनाव आयोग ने मंगलवार को असम में हुए स्पेशल रिवीजन 2026 के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी। चुनाव आयोग के मुताबिक,ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तुलना में 2.43 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। अब राज्य में कुल 2,49,58,139 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मतदाताओं की संख्या 2,52,01,624 थी। स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया के बाद लिस्ट में 2,43,485 नाम हटाए गए हैं। अब फाइनल लिस्ट में 1,24,82,213 पुरुष, 1,24,75, 583 महिलाएं और 343 थर्ड-जेंडर शामिल हैं। स्पेशल रिवीजन की इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 27 दिसंबर 2025 को पब्लिश हुई थी। इस पर

27 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां करने का समय था। असम की 126 विधानसभा सीटों पर अगले तीन महीनों में चुनाव होने हैं। असमें 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2025 तक पूरे राज्य में घर-घर वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया था। इससे पहले चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की टाइमलाइन में बदलाव करते हुए फाइनल पब्लिकेशन की तारीख 14 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी थी। आयोग ने यह फैसला बड़े पैमाने पर गणना कार्य और पोलिंग स्टेशनों के वेरिफिकेशन व रैशनलाइजेशन की जरूरत को देखते हुए लिया था। चुनाव आयोग ने दोहराया है कि सभी नागरिकों को SIR प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए, ताकि सटीक और अपडेटेड इलेक्टोरल रोल सुनिश्चित किए जा सकें,जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की बुनियाद हैं।

देश में जानबूझकर अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा विपक्ष : भाजपा

नई दिल्ली,10 फरवरी 2026। संसद में हंगामे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर देश में जानबूझकर अस्थिरता का माहौल बनाने के प्रयास का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद डॉ. संबित पात्रा ने यहां पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि सभी देख रहे हैं कि मीडिया में किस प्रकार सदन में हो रही गतिविधियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। पूरे देश में विपक्ष जानबूझकर अस्थिरता का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सब आज से नहीं हो रहा, बल्कि जब से भाजपा-नीत राजग की सरकार बनी है, तब से राहुल गांधी, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जॉर्ज सोरोस के इशारों पर देश के संवैधानिक संस्थानों पर गातार हमले कर रहे हैं। ये देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड : मुंबई की कोर्ट ने 27 आरोपियों के खिलाफ तय किए आरोप

नई दिल्ली,10 फरवरी 2026। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मंगलवार को एक विशेष अदालत ने 27 आरोपियों के खिलाफ मकोका और बीएनएस के तहत आरोप तय किए। सिद्दी की साल 2024 में हत्या कर दी गई थी। वहीं, आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया।

किन कानूनों के तहत आरोप तय किए गए : विशेष जज सत्यनारायण आर नवंदर ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं,महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका),आयुध अधिनियम और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत आरोप तय किए। भारतीय नागरिक

सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत आरोप तय करना आपराधिक मुकदमे का पहला चरण है, जहां कोर्ट सबूतों के आधार पर आरोपों को औपचारिक रूप देती है। बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को बांद्रा के निर्मल नगर इलाके में हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनके बेटे जीशान के कार्यालय के बार उन्हें गोली मारी थी।

मथुरा में परिवार के 5 लोगों की लाश मिली पति-पत्नी, 3 बच्चे

मथुरा,10 फरवरी 2026। मथुरा में एक ही कमरे से एक परिवार के 5 लोगों की लाशें मिलीं। मृतकों में पति, पत्नी और 3 बच्चे शामिल हैं। कमरे में बेड पर मां,एक बेटी-बेटा मिले। दूसरी बेटी चारपाई पर पड़ी थी, जबकि पति का शव फर्श पर मिला। पुलिस के अनुसार,पति ने पहले पत्नी की हत्या की, फिर बच्चों की जान ली। बाद में खुद करंट लगाकर आत्महत्या कर ली। SSP श्लोक कुमार ने बताया कि घटना का पता उस समय चला,जब सुबह बच्चे दिखाई नहीं दिए। इस पर पड़ोस में रहने वाले मनीष के भाई जयकिशन मौके पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद होने की वजह से जयकिशन मेन गेट फांदकर अंदर गए।

साइबर सुरक्षा देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा : शाह

नई दिल्ली,10 फरवरी 2026। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के एक कार्यक्रम में कहा कि साइबर सुरक्षा अब केवल तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है बल्कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा से सीधे तौर पर जुड़ चुका है। देश के डेटा को हर हाल में सुरक्षित करना होगा। सीबीआई ने आयोजित साइबर सक्षम धोखाधड़ी से निपटने और उसके पूरे तंत्र को ध्वस्त करने के विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन यहां 10 और 11 फरवरी तक चलेगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीबीआई के नए साइबर अपराध प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया। साथ ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र

(आई4सी) के अंतर्गत स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (एस4सी) डैशबोर्ड की भी शुरुआत की। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि यह दोनों ऐसी इकाइयां हैं,जिसमें अलग-अलग विभाग और एजेंसियां एक ही प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध से निपटने के लिए काम कर रही हैं। जब सभी प्रयास एक दिशा में होते हैं,तभी अपेक्षित परिणाम मिलते हैं। पिछले 11 वर्षों की भारत की डिजिटल यात्रा में साइबर सुरक्षा सबसे अहम विषय बनकर उभरी है। अमित शाह ने कहा कि पहले देश में डिजिटल सेवाओं के करीब 25 करोड़ उपयोगकर्ता थे, जो अब 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। एक जीबी डेटा की कीमत में करीब 97 प्रतिशत की कमी आई है। दुनिया के हर दूसरे डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। 97 करोड़ से अधिक जनधन खातों और देश के संगठनों के संवेदनशील डेटा की सुरक्षा अब बड़ी चुनौती है। गृह मंत्री ने बताया कि हाल के वर्षों में सीबीआई ने 20 हजार करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामलों की जांच की है, जिनमें से 8 हजार करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज किया गया है।

संपादकीय

भारत का राष्ट्रीय मिशन बना महाशक्ति बनने का कारण

भारत के पास चीन और ब्राजील के बाद दुर्लभ खनिजों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है, जबकि अमेरिका इस मामले में विश्व में सातवें नंबर पर है। ट्रंप साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग कर ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रयास में इसलिए जुटे, क्योंकि ग्रीनलैंड के पास विश्व का आठवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों का भंडार है...

कुछ समय पहले भारी मुनाफा कमाने वाली एक भारतीय कंपनी ने एक छोटी सी चीनी कंपनी से सौर ऊर्जा से जुड़ी तकनीक खरीदनी चाही, परंतु उसने देने से मना कर दिया। यह तब हुआ,जब भारत अंतरराष्ट्रीय सोलर एलायंस का संस्थापक है। भारत ने फ्रांस के साथ इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 2015 में की थी। यह अपनी तरह का पहला बड़ा संगठन है, जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है। इसका उद्देश्य 125 सदस्य देशों के साथ मिलकर 2030 तक सौर ऊर्जा उत्पादन में एक ट्रिलियन डॉलर का निवेश और 1000 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन है। चीन को कई बार इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया,पर उसने स्वीकार नहीं किया।

विडंबना यह है कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन के अगुआ भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक को चीन की छोटी सी कंपनी के पास ही सौर ऊर्जा से जुड़ी तकनीक मांगने जाना पड़ा। इसका कारण यह है कि हजारों करोड़ रुपये प्रति तिमाही का मुनाफा कमा रही भारतीय कंपनियां भी नई तकनीक के अनुसंधान में भारत में निवेश नहीं करना चाहती हैं। वे खुदरा माल-सेवाओं के आपूर्तिकर्ता मात्र के रूप में अपने व्यापार का विस्तार कर रही हैं और टेक्नोलाजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। इसी कमजोरी के चलते हम विश्व स्तर पर नेतृत्व देने में अक्षम हैं। विश्व शक्तियां हमें अक्षम ही बने रहने देना चाहती हैं। इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के नेतृत्व वाला पैक्स सिलिका गठजोड़ है।

पैक्स सिलिका महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में काम आने वाले दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति और प्रसंस्करण से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं को पिरोकर चीन जैसे देशों के इस क्षेत्र पर नियंत्रण से निकलने के उद्देश्य से बनाया गया है। पहले भारत ने इससे जुड़ने की इच्छा जताई थी,परंतु ट्रंप प्रशासन ने उसे नकार दिया था। इस पर भारत के कुछ उद्योगपतियों ने कहा था कि यदि सरकार उनके साथ सहयोग करे तो वे दुर्लभ खनिजों का खनन और प्रसंस्करण भारत में कर सकते हैं।

भारत के पास चीन और ब्राजील के बाद दुर्लभ खनिजों का विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार है,जबकि अमेरिका इस मामले में विश्व में सातवें नंबर पर है। ट्रंप साम-दाम-दंड-भेद का प्रयोग कर ग्रीनलैंड पर कब्जे के प्रयास में इसलिए जुटे,क्योंकि ग्रीनलैंड के पास विश्व का आठवां सबसे बड़ा दुर्लभ खनिजों का भंडार है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को हासिल भी कर ले तब भी 3.4 मीट्रिक टन के साथ उसका स्थान सातवां ही रहेगा।

विचारणीय यह है कि दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में भारत को अमेरिका का पिछलग्गू बनना चाहिए या आत्मनिर्भर? जैसे ही भारतीय उद्योगपतियों ने स्वयं इन खनिजों के खनन और प्रसंस्करण करने की बात कही, अमेरिका ने तुरंत अपनी चाल बदलकर भारत को पैक्स सिलिका में जुड़ने के लिए आमंत्रित कर लिया। इसकी वकालत करने वाली एक लाबी के अनुसार इन दुर्लभ खनिजों का खनन और प्रसंस्करण बहुत जटिल प्रक्रिया है,इसलिए भारत का अमेरिका की अगुआई में काम करना आसान रहेगा,पर जब हमें यह सब आसानी से उपलब्ध होने लगेगा तो हम शिथिल पड़ जाएंगे और खनन और प्रसंस्करण तकनीकी में निवेश ही नहीं करेंगे। प्रश्न यह है कि इस जटिल काम को चीन ने कैसे कर लिया?

चीन 1986 में ही अमेरिका को पीछे छोड़ दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था। 1985-95 के बीच चीन में इन खनिजों का उत्पादन 464 प्रतिशत बढ़ा। 2004 आते-आते चीन विश्व भर के 90 प्रतिशत दुर्लभ खनिजों का निर्यातक बन चुका था। आज चीन विश्व दुर्लभ खनिजों का 70 प्रतिशत खनन,90 प्रतिशत शोधन और रेयर अर्थ मैग्नेट के 90 प्रतिशत उत्पादन को नियंत्रित करता है। जो काम चीन 1980-90 के दशक में कर पाया वह हम आज क्यों नहीं कर सकते? आत्मनिर्भरता क्या आत्मसंदेह से आएगी। जब विश्व ने परमाणु तकनीक भारत को देने से मना कर दिया था तो क्या हमने परमाणु बम नहीं बना लिया था? इसके उलट उदाहरण भी देख लीजिए।

हम हमेशा फाइटर जेट विदेश से आयात करते रहे हैं। इसके चलते हम आज तक इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं,जबकि विश्व की हर महाशक्ति अमेरिका,रूस,फ्रांस,यूरोपीय संघ,चीन अपने फाइटर जेट और उसके इंजन स्वयं बनाते हैं। खबरें हैं कि भारत को एक बार फिर लाखों करोड़ रुपये खर्च करके फ्रांस,रूस या अमेरिका में से किसी एक से फाइटर जेट आयात करने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों के बस अब मात्र 29 स्क्वाड्रन ही बाकी रह गए हैं,जबकि होने कम से कम 42 स्क्वाड्रन चाहिए। यह स्थिति इसलिए है,क्योंकि तेजस का उत्पादन समय से नहीं हो पाया और स्वदेशी जेट इंजन बनाने का कार्यक्रम भी अधूरा ही रहा।

1989 में प्रारंभ किए गए कावेरी जेट इंजन कार्यक्रम में भारत ने 2008 तक मात्र 2000 करोड़ रुपये का निवेश किया और फिर उसे असफल पाकर तेजस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। पिछले 40 साल में भारत ने कावेरी इंजन कार्यक्रम पर अधिकतम 5000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं,जबकि चीन तीन लाख पचास हजार करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। आज चीन के पास छठी पीढ़ी के स्वनिर्मित लड़ाकू विमान जे-20 के लिए अपना जेट इंजन तैयार है, जबकि हम चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान विदेश से खरीदने के लिए तीन-चार लाख करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। क्या कोई यह वादा कर सकता है कि हम अंतिम बार विदेशी लड़ाकू विमान खरीदने जा रहे हैं?

चीन छठी पीढ़ी के 100-120 लड़ाकू विमान बना रहा है और हम चौथी पीढ़ी के 6-12 जहाज बना पा रहे हैं। कारण यह है कि इसके इंजन के लिए हम अमेरिका पर निर्भर हैं। तीन-चार लाख करोड़ रुपये विदेशी लड़ाकू विमानों पर खर्च करने के बाद हमारी सरकार स्वदेशी जेट इंजन के विकास पर कितना खर्च कर पाएगी,यह भी विचारणीय है। जब तक इन सेक्टरों में आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय मिशन नहीं बनाया जाएगा,तब तक भारत के एक आत्मनिर्भर विश्वशक्ति बनने पर प्रश्नचिह्न लगा रहेगा। भारत के महाशक्ति बनने का मार्ग आसान नहीं है और न ही आसान रास्ते से महाशक्ति बना जा सकता है।

प्रकृति,पैसा और स्वास्थ्य: एक संतुलित दृष्टि

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार,हरियाणा

आज के दौर में स्वास्थ्य को लेकर हमारी सोच तेजी से बदली है। आधुनिक जीवन शैली,तकनीक,महंगी चिकित्सा सुविधाएँ और बढ़ती आय ने यह विश्वास पैदा कर दिया है कि पैसा ही बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है। बड़े शहरों में रहने वाला व्यक्ति मानता है कि यदि उसके पास अच्छे अस्पताल,नामी डॉक्टर,निजी बीमा और आधुनिक उपकरण हैं, तो बीमारी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब हम देखते हैं कि देश-दुनिया की नामचीन हस्तियाँ–जिनके पास धन, संसाधन और सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध थीं–गंभीर बीमारियों का शिकार हुईं, तो यह विश्वास डगमगाने लगता है। यह प्रश्न स्वाभाविक है कि आखिर इतनी देखभाल,इतनी सावधानी और इतने संसाधनों के बावजूद भी लोग कैंसर,हृदय रोग और अन्य जटिल बीमारियों से क्यों नहीं बच पाए। क्या आधुनिक जीवनशैली वास्तव में हमें स्वस्थ बना रही है, या हम अनजाने में अपने शरीर की प्राकृतिक शक्ति को कमजोर कर रहे हैं?यह सवाल केवल अमीर और मशहूर लोगों तक सीमित नहीं है,बल्कि हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जो तेज़ रफ्तार,कृत्रिम और तनावपूर्ण जीवन जी रहा है।

मानव शरीर प्रकृति की देन है और लाखों वर्षों के विकास का परिणाम है। हमारा शरीर प्राकृतिक भोजन,शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी,धूप और शारीरिक श्रम के साथ तालमेल बैठाकर विकसित हुआ है। जब हम इस प्राकृतिक संतुलन से दूर होते जाते हैं–अत्यधिक प्रोसेस्ड भोजन खाते हैं,घंटों बंद कमरों में रहते हैं,मोबाइल और स्क्रीन के सामने जीवन बिताते हैं–तो शरीर का संतुलन बिगड़ने लगता है। बीमारियाँ अचानक नहीं आतीं,वे वर्षों की गलत आदतों,तनाव और असंतुलन का परिणाम होती हैं। आज का भोजन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पैकेट में बंद,लंबे समय तक टिकने वाला और स्वाद बढ़ाने वाले रसायनों से भरपूर भोजन हमारी थाली में जगह बना चुका है। फल के नाम पर जूस,सब्जियों के नाम पर फ्रोजन पैक और दूध के नाम पर प्रोसेस्ड उत्पाद हमारे दैनिक आहार का हिस्सा बन गए हैं। यह सुविधाजनक ज़रूर है,लेकिन शरीर के लिए हमेशा हितकारी नहीं। प्रकृति हमें भोजन उसके संपूर्ण रूप में देती है–जिसमें फाइबर, विटामिन और पोषक तत्व संतुलित होते हैं। जब हम उस रूप को बदल देते हैं, तो उसका प्रभाव भी बदल जाता है।

स्वच्छता और सुरक्षा के नाम पर हमने अपने आसपास का वातावरण भी अत्यधिक कृत्रिम बना लिया है। हर चीज़ को कीटाणुरहित करने की होड़ लगी है। साबुन,सैनिटाइज़र और केमिकल क्लीनर के बिना जीवन अधूरा सा लगने लगा है। इसमें संदेह नहीं कि स्वच्छता आवश्यक है,लेकिन अति हमेशा हानिकारक होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सीमित मात्रा में प्राकृतिक बैक्टीरिया से संपर्क हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। जो शरीर हर छोटी चुनौती से बचा लिया जाता है,वह बड़ी चुनौती आने पर कमजोर पड़ सकता है।

ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन की तुलना इस संदर्भ में अक्सर की जाती है। गाँवों में रहने वाले बुज़ुर्ग अपेक्षाकृत सादा भोजन करते हैं, शारीरिक श्रम अधिक होता है और जीवन की गति धीमी होती है। मानसिक तनाव भी अपेक्षाकृत कम होता है। यही कारण है कि छोटी-मोटी बीमारियाँ वे बिना दवा के भी झेल लेते हैं। वहीं शहरों में रहने वाला व्यक्ति आरामदायक जीवन जीता है,लेकिन एक साधारण बुखार भी उसे बिस्तर से बाँध देता है। यह अंतर केवल चिकित्सा सुविधाओं का नहीं,बल्कि जीवनशैली और मानसिक स्थिति का भी है।

हालाँकि यह मान लेना भी गलत होगा कि प्रकृति से जुड़ाव ही हर बीमारी का इलाज है। कई बीमारियाँ आनुवंशिक होती हैं,कई संक्रमण के कारण होती हैं और कई उम्र के साथ स्वाभाविक रूप से आती हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने इन क्षेत्रों में अभूत पूर्व प्रगति की है। टीके, एंटीबायोटिक,सर्जरी और आधुनिक जांच तकनीकों ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। यदि हम केवल प्राकृतिक के नाम पर विज्ञान को नकार दें,तो यह भी एक खतरनाक सोच होगी।

असल समस्या तब पैदा होती है जब हम किसी एक छोर पर चले जाते हैं। या तो हम पूरी तरह मशीनों, दवाओं और सुविधाओं पर निर्भर हो जाते हैं, या फिर विज्ञान को नकारकर हर समस्या का समाधान केवल घरेलू नुस्खों में खोजने लगते हैं। दोनों ही दृष्टिकोण अधूरे हैं। स्वास्थ्य एक संतुलन का नाम है–जहाँ प्रकृति और विज्ञान दोनों की अपनी-अपनी भूमिका है।

मानसिक स्वास्थ्य इस संतुलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसे अक्सर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। आज का इंसान शारीरिक रूप से भले ही सुविधाओं से घिरा हो, लेकिन मानसिक रूप से असुरक्षित,चिंतित और तनावग्रस्त है। प्रतिस्पर्धा, असफलता का डर,सामाजिक दबाव और भविष्य की चिंता हमारे मन को लगातार व्यस्त रखते हैं। यह मानसिक तनाव धीरे-धीरे शरीर पर असर डालता है और गंभीर बीमारियों का कारण बनता है। पैसा इस तनाव को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता।

यह भी समझना ज़रूरी है कि अमीर लोगों की बीमारियाँ हमें ज़्यादा इसलिए दिखती हैं क्योंकि वे सार्वजनिक जीवन में होते हैं। आम लोगों में भी वही बीमारियाँ होती हैं, लेकिन वे चर्चा में नहीं आतीं। इसका अर्थ यह नहीं कि धन अपने आप बीमारी लाता है,बल्कि यह कि धन बीमारी से पूर्ण सुरक्षा नहीं दे सकता। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम स्वास्थ्य को केवल इलाज की दृष्टि से न देखें,बल्कि जीवनशैली की दृष्टि से समझें। सादा और संतुलित भोजन, नियमित शारीरिक गतिविधि,पर्याप्त नींद,प्रकृति के साथ समय और मानसिक शांति–ये सब किसी भी दवा से कम प्रभावी नहीं हैं। इसके साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर समय पर डॉक्टर से सलाह लेना और आधुनिक चिकित्सा का लाभ उठाना भी उतना ही ज़रूरी है।

अंततः यह स्वीकार करना होगा कि न तो पैसा हमें अमर बना सकता है और न ही केवल प्राकृतिक जीवनशैली सभी बीमारियों से बचा सकती है। असली समाधान संतुलन में है। जब हम प्रकृति की समझ के साथ विज्ञान को अपनाते हैं, तब ही स्वस्थ और सार्थक जीवन संभव है। शायद यही वह रास्ता है, जिस पर चलकर हम न केवल लंबा, बल्कि बेहतर जीवन भी जी सकते हैं।

लोकसभा-अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास : लोकतंत्र की अग्निपरीक्षा

ललित गर्ग
पटपड़गंज,दिल्ली-92

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी लोकतंत्र के लिये एक चिन्ताजनक घटना है। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक प्रणाली नहीं,बल्कि निरंतर संवाद,असहमति के सम्मान और संस्थागत विश्वास पर टिकी हुई एक जीवंत परंपरा है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में संसद इस लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है,जहाँ न केवल नीतियाँ बनती हैं,बल्कि राष्ट्र की आत्मा बोलती है। ऐसे में जब लोकसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की खबरें सामने आती हैं,तो यह घटना किसी एक व्यक्ति या दल तक सीमित न रहकर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देती है। विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जाना कि उन्हें, विशेषकर नेता प्रतिपक्ष को, सदन में बोलने का समुचित अवसर नहीं मिल रहा,और इसी आधार पर अध्यक्ष की निष्पक्षता पर सवाल उठाना,एक गहरी चिंता का विषय है। यह चिंता इसलिए भी अधिक गंभीर हो जाती है क्योंकि अध्यक्ष का पद परंपरागत रूप से सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन का प्रतीक माना जाता रहा है।

लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका केवल कार्यवाही संचालित करने तक सीमित नहीं होती,बल्कि वह सदन की गरिमा,लोकतांत्रिक मर्यादा और सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की संवैधानिक जिम्मेदारी भी निभाते हैं। यदि विपक्ष का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करने लगे कि अध्यक्ष का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है या उनकी आवाज को व्यवस्थित रूप से दबाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीतिक असंतोष नहीं, बल्कि संस्थागत अविश्वास का संकेत होता है। 100 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षर कर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी यह दर्शाती है कि मामला क्षणिक आक्रोश का नहीं, बल्कि लंबे समय से पनप रही असहमति और संवादहीनता का परिणाम है।

लोकसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक की भूमिका में होते हैं, जिनके प्रति विश्वास जरूरी होता है और उनसे भी निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है। हालांकि यह भी उतना ही सत्य है कि संख्या बल के आधार पर इस तरह का प्रस्ताव पारित होना कठिन है,लेकिन लोकतंत्र में कई बार प्रतीकात्मक कदम भी गहरे संदेश देते हैं।

विपक्षी दलों द्वारा यह स्पष्ट करना कि वे टकराव के साथ-साथ सुलह का विकल्प भी खुला रखे हुए हैं,और इसी क्रम में विभिन्न वरिष्ठ नेताओं का अध्यक्ष से मुलाकात कर संवाद का प्रयास करना,इस बात का संकेत है कि अभी भी समाधान की गुंजाइश समाप्त नहीं हुई है। यह स्थिति हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर संवाद की जगह हंगामा, नारेबाजी और गतिरोध क्यों हावी होता जा रहा है। क्या यह केवल सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास का परिणाम है,या फिर संसदीय परंपराओं के क्षरण का संकेत? विगत वर्षों में बार-बार यह देखने को मिला है कि महत्वपूर्ण विधेयकों और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर गंभीर चर्चा के बजाय सदन की कार्यवाही बाधित होती रही है। इससे न केवल विधायी कामकाज प्रभावित होता है,बल्कि जनता के बीच यह संदेश भी जाता है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि अपने दायित्वों के प्रति गंभीर नहीं हैं।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि वह असहमति को स्थान देता है। विपक्ष का काम केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार को जवाबदेह ठहराना और वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना भी है। इसके लिए सदन में बोलने का अवसर, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और आलोचना का सम्मान अनिवार्य है। यदि विपक्ष यह महसूस करता है कि उसके लिए ये रास्ते संकुचित किए जा रहे हैं,तो उसका आक्रोश सड़कों या नारेबाजी के रूप में फूट पड़ता है,जो अंततः संसद की गरिमा को ही नुकसान पहुँचाता है। दूसरी ओर,विपक्ष द्वारा बार-बार सदन की कार्यवाही बाधित करना भी उतना ही गंभीर दोष है,क्योंकि इससे शासन की प्रक्रिया ठप्प होती है और जनता के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। इस दोतरफा अविश्वास और आक्रामकता के बीच लोकतंत्र का मूल उद्देश्य कहीं खोता हुआ दिखता है।

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में यदि संसद बार-बार हंगामे, निलंबन और गतिरोध की खबरों में रहे,तो यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की लोकतांत्रिक छवि को प्रभावित करता है। विकास,नीति और जनकल्याण की चर्चा के स्थान पर यदि टकराव और अविश्वास केंद्र में आ जाए,तो यह भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती केवल मजबूत सरकार से नहीं,बल्कि मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष संस्थानों से भी आती है। लोकसभा अध्यक्ष जैसे पद से अपेक्षा की जाती है कि वह न केवल नियमों का पालन कराए, बल्कि विश्वास का सेतु भी बने। वहीं विपक्ष से भी यह अपेक्षा है कि वह विरोध को रचनात्मक बनाए, न कि अवरोध का माध्यम।

आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद को फिर से संवाद का मंच बनाया जाए,जहाँ तीखी असहमति भी मर्यादा में व्यक्त हो और सत्ता व विपक्ष दोनों ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराएँ। अविश्वास प्रस्ताव जैसे कदम यदि चेतावनी के रूप में लिए जा रहे हैं, तो उन्हें आत्ममंथन का अवसर भी बनना चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि यह है कि लोकतंत्र की संस्था को कैसे स्वस्थ, विश्वसनीय और प्रभावी बनाया जाए। जनता ने सांसदों को नारे लगाने या कार्यवाही बाधित करने के लिए नहीं,बल्कि देश के भविष्य पर गंभीर विमर्श के लिए चुना है। यदि संसद इस अपेक्षा पर खरी नहीं उतरती,तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है।

यह भी तथ्य है कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में श्री ओम बिरला का संसदीय संचालन अब तक सामान्यतःअनुशासित, कार्यकुशल और नियमसम्मत माना जाता रहा है। उनके कार्यकाल में लोकसभा की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने,विधायी कार्यों को प्राथमिकता देने और विभिन्न दलों को साथ लेकर चलने का प्रयास स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अनेक अवसरों पर उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है तथा संसदीय परंपराओं और नियमों के पालन पर बल दिया है। उनकी छवि एक ऐसे अध्यक्ष की रही है जो सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए होशियारी, धैर्य और व्यावहारिक समझ का प्रयोग करते हैं। लोक तांत्रिक संस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता,संसदीय मर्यादाओं का आग्रह और संवाद के लिए दरवाजा खुले रखने की प्रवृत्ति को देखते हुए उनके जैसे लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति अपने आप में एक त्रासद और चिंताजनक घटना प्रतीत होती है। यह घटना व्यक्ति विशेष से अधिक उस माहौल की ओर संकेत करती है, जहाँ अविश्वास इतना गहरा हो चुका है कि संवाद और विश्वास के पुल कमजोर पड़ते जा रहे हैं।

अंततः यह समय आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर जिम्मेदारी स्वीकार करने का है। सत्तापक्ष को यह समझना होगा कि मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की कमजोरी नहीं,बल्कि उसकी ताकत है। विपक्ष को यह स्वीकार करना होगा कि विरोध की भी एक मर्यादा और रचनात्मकता होती है। और अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पदों को यह स्मरण रखना होगा कि उनकी निष्पक्षता केवल नियमों के पालन से नहीं, बल्कि व्यवहार और अवसर की समानता से भी सिद्ध होती है। यदि संसद को संवाद का मंच बनाए रखने में हम विफल रहते हैं, तो यह केवल एक सत्र या एक सरकार की विफलता नहीं होगी, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक असफलता मानी जाएगी। यही वह बिंदु है जहाँ हर नागरिक, हर जनप्रतिनिधि और हर संस्था को आत्मचिंतन करना होगा, ताकि विकास की राह में विनाश की संभावनाएँ नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और लोकतांत्रिक परिपक्वता का मार्ग प्रशस्त हो सके।

डिजिटल युग अच्छा भी और बुरा भी

सुभाष बुड़ावनवाला
रतलाम,मध्यप्रदेश

डिजिटल युग ने जहां जीवन को आसान बनाया है,वहीं साइबर धोखाधड़ी के मामलों में भी चिंताजनक वृद्धि हुई है। विशेष रूप से डिजिटल अरेस्ट जैसी नई ठगी पद्धति ने आम लोगों की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिया है। इस तरह की धोखाधड़ी में अपराधी खुद को पुलिस,सीबीआइ या किसी सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल या फोन के माध्यम से लोगों को डराते हैं और उन्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे किसी गंभीर अपराध में फंस चुके हैं। भय और मानसिक दबाव में आकर कई लोग अपनी जीवनभर की कमाई ठगों के हवाले कर देते हैं। ऐसे मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीबीआइ, बैंकों और रिजर्व बैंक के रवैये पर नाराजगी जताना यह संकेत देता है कि साइबर सुरक्षा तंत्र अभी अपेक्षित स्तर तक मजबूत नहीं हो पाया है। यदि बैंक समय पर संदिग्ध लेन-देन को रोकने और खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई करें, तो ठगी के अनेक मामलों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम विकसित हो चुके हैं, जो असामान्य लेन-देन की तुरंत पहचान कर सकते हैं। विकसित देशों में रियल-टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग और बिहेवियरल एनालिटिक्स जैसे उपायों से साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया गया है,और भारत में भी इन्हें व्यापक रूप से लागू करने की आवश्यकता है।

सरकार ने साइबर ठगी से बचाव के लिए 1930 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल जैसी सुविधाएं शुरू की हैं,जहां त्वरित शिकायत दर्ज कराकर रकम को ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा, म्यूल अकाउंट्स यानी ऐसे बैंक खातों पर सख्ती जरूरी है,जिन्हें अपराधी चोरी के पैसे को इधर-उधर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बैंकों को अपने केवाईसी मानकों को और कठोर बनाना होगा तथा संदिग्ध खातों की नियमित ऑडिट करनी होगी।

हालांकि तकनीकी उपायों के साथ-साथ जन-जागरूकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोगों को यह समझना होगा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल पर पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देती। अनजान लिंक पर क्लिक करने, स्क्रीन शेयर करने या ओटीपी बताने से बचना चाहिए। मोबाइल और बैंकिंग ऐप्स में टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग तथा समय-समय पर पासवर्ड बदलना भी सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक है।

स्पष्ट है कि साइबर धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए केवल अदालत की सख्ती पर्याप्त नहीं होगी। इसके लिए बैंकों,नियामक संस्थाओं, सरकार और आम नागरिक–सभी को मिलकर एक सशक्त डिजिटल सुरक्षा संस्कृति विकसित करनी होगी। जब तक तकनीकी सतर्कता,संस्थागत जवाबदेही और नागरिक जागरूकता का समन्वय नहीं होगा, तब तक डिजिटल अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता खतरे में बनी रहेगी।

विशेषता बिहार के मुजफ्फरपुर की...

मुस्कान केशरी
मुजफ्फरपुर बिहार

बिहार की राजधानी पटना से मात्र 65-70 किलोमीटर की दूरी पर मुजफ्फरपुर जिला बसा है और आज मै आप सभी को मुजफ्फरपुर के बारे में बताने वाली हुँ। मुजफ्फरपुर का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविध रहा है। प्राचीन काल में,यह शहर मिथिला राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था,जो बाद में वज्जि गणराज्य का हिस्सा बन गया । मध्ययुगीन काल में, मुजफ्फरपुर पर विभिन्न राजवंशों का शासन रहा,जिनमें पाल वंश, सेन वंश और तुगलक वंश शामिल है। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद,यह शहर अंग्रेजी हुकूमत के अधीन हो गया। मुजफ्फरपुर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी अपनी भूमिका निभाई है। खुदीराम बोस,जुब्बा साहनी और पंडित सहदेव झा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस शहर में अपनी गतिविधियाँ चलाई है। वैसे तो मुजफ्फरपुर

जिला की स्थापना 1 जनवरी 1875 में ब्रिटिश राज के दौरान प्रशासनिक सुविधा के लिए तिरहुत जिले को विभाजित करके की गई थी और इसका नाम एक औमिल मुजफ्फर खान के नाम पर रखा गया था, इस प्रकार इस शहर को मुजफ्फरपुर के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे तो इस शहर को लीची की भूमि भी कहा जाता है और विश्व में भारत देश के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला को मीठा शहर के नाम से जाना जाता है। क्योंकि बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में लीची की उत्पादक अधिक की जाती है इसलिए। इस जिला में मुख्य रूप से नवीन जलोढ़ मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से यह मिट्टी मुजफ्फरपुर,दरभंगा और चंपारण में पाया जाता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र का एक प्रमुख शहर है मुजफ्फरपुर और तिरहुत मंडल का मुख्यालय भी है। मुजफ्फरपुर जिला का सबसे बड़ा गाँव जजुआरा है जिसे हम जजुआर और यजुआर भी कहते है और यह बिहार का दूसरा सबसे बड़ा गाँव है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक,बागमती, लखनदेई और गंडक नदी बहती है। मुजफ्फरपुर अभी व्यावसायिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं,जो अपने सूती वस्त्र उद्योग,लाह की चूड़ियों,शहद, लीची और फलों के लिए प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर में घूमने के लिए कई आकर्षक स्थल है जैसे शीतलढी आश्रम,बाबा गरीब नाथ मंदिर,देवी मंदिर,वैष्णो माता मंदिर,सरस्वती मंदिर,माँ काली मंदिर,गुरुद्वारा, मस्जिद,चार्च,मोती झील बाजार, खुशरूपुर,कटरा गरीबनाथ मेला, राजकीय संग्रहालय,जुब्बा साहनी पार्क,इंद्ररा पार्क,सीटी पार्क इत्यादि। इसके अलावा आर्मी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के लिए जिला स्कूल का मैदान,एल एस काँलेज का मैदान, नेहरू स्टेडियम का मैदान है जहाँ अभ्यर्थी मेहनत करते हैं और अपने सपने को पूरा करके राष्ट्र सेवा में लग जाते हैं। मुजफ्फरपुर में कई प्रसिद्ध विद्यालय है जैसे चैपमैन स्कूल,जिला स्कूल, मुखर्जी सेमनेरी स्कूल इत्यादि और कई महाविद्यालय है जहाँ एम डी डी एम काँलेज,एल एस काँलेज,आर डी एस काँलेज, एल एन टी काँलेज इत्यादि। मुजफ्फरपुर अपनी पारंपरिक कला के लिए भी जाना जाता है। यह शहर लोकनृत्य,लोकगायन,साहित्य,पर्यावरण, कठपुतली व विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दे रहा है। एक मुजफ्फरपुर आए और मीठी लीची खाए। जल्द से जल्द मुजफ्फरपुर आए और इस शहर को घूमें।

कविता

पीत सरसों धरा को

त्रिशिका धरा
कानपुर, उत्तर प्रदेश

पीत सरसों धरा को सजाने लगी
कोकिला भी मधुर गीत गाने लगी
मेरे केशों से,अधरों से है खेलती
रुत बसंती सजन सी सताने लगी
इस बरस उम्र सोलह लगी है जिसे
वो कली भंवरे का चित चुराने लगी
पत्ते वीणा सी झंकार करने लगे
बाग में रास बुलबुल रचाने लगी
खेत की मेड़ पर साथ चलना तेरा
वो घड़ी बिरहा में याद आने लगी
हाथ मुझ से छुड़ा कर गया जब से तू
हरखुशी मुझसे दामन छुड़ाने लगी
मेरे हृदय ने ऐसे पुकारा तुझे
जैसे मोहन को राधा बुलाने लगी

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

भीषण आगजनी में तीन दुकानें जलकर खाक

फर्नीचर शोरूम से शुरू हुई आग ने दो अन्य दुकानों को लिया चपेट में

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के अंबेडकर चौक के समीप मंगलवार तड़के भीषण आगजनी की घटना में एक फर्नीचर शोरूम,सेकेंड हैंड दोपहिया वाहन शोरूम और एक होटल जलकर खाक हो गया। तीनों प्रतिष्ठान एक ही लाइन में स्थित थे और अल्बेस्टर शीट से निर्मित होने के कारण आग तेजी से फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत संभवतः मारुति फर्नीचर शोरूम से हुई, जिसने देखते ही देखते आसपास के होटल और निहारिका ऑटोडील सर्विसिंग सेंटर को भी अपनी चपेट में ले लिया। होटल में रखे दो गैस सिलेंडरों के फटने से आग और विकराल हो गई। जानकारी के अनुसार गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अंबेडकर चौक के पास स्थित मारुति फर्नीचर शोरूम का संचालन एमजी रोड निवासी राकेश अग्रवाल करते हैं। शोरूम में फर्नीचर के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऑटो ई-रिक्शा का भी कारोबार किया जाता था। इसके दोनों ओर चाय-नाश्ते का होटल तथा निहारिका ऑटोडील सर्विसिंग सेंटर संचालित है, जिसका संचालन सुनील व सुशील गोयल करते हैं। सोमवार रात सभी संचालक अपनी-अपनी दुकानें बंद कर घर चले गए थे। मंगलवार सुबह करीब 4.30 बजे राहगीरों ने शोरूम में आग लगने की सूचना संचालक को दी। सूचना मिलते ही संचालक परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे,लेकिन तब तक आग तीनों दुकानों में फैल चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और गांधीनगर थाना पुलिस को सूचना दी गई। दमकल टीम करीब सुबह 5 बजे मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। लगभग चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका। तब तक तीनों प्रतिष्ठान पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुके थे। सबसे अधिक नुकसान मारुति फर्नीचर शोरूम को हुआ है।

गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी

आग होटल तक पहुंचने के बाद वहां रखे दो गैस सिलेंडर एक-एक कर जोरदार धमाके के साथ फट गए। सिलेंडरों के टुकड़े दूर तक जा गिरे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। फर्नीचर शोरूम में बड़ी मात्रा में सामान भरा हुआ था। आग की चपेट में आने से ऑटो ई-रिक्शा,अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक सामग्री सहित अन्य फर्नीचर जलकर खाक हो गया। संचालक को भारी आर्थिक नुकसान होने की बात कही जा रही है।

आग बुझाने में लगा 10 टैंकर पानी

आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के टैंकरों के साथ पुलिस विभाग के वज्र वाहन, आडानी तथा एयरपोर्ट से दमकल वाहनों की सहायता ली गई। करीब 10 टैंकर पानी का उपयोग किया गया। आग बुझने के बाद भी दोपहर तक धुआं निकलता रहा। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

लाइसेंसी बंदूक लूट का आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार

कसाबेल से पकड़ा गया आरोपी, लूटी गई बंदूक बरामद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

नवापारा क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड से लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक लूटने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कसाबेल (जिला जशपुर) से पकड़ा गया, जिसके कब्जे से लूटी गई बंदूक भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के अनुसार प्रार्थी अमोद कुमार एक्का, जो पंजाब एंड सिंध बैंक अंबिकापुर में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्यरत हैं, 8 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे अपने पुराने किराये के मकान नवापारा से नया सामान शिफ्ट कर रहे थे। ऑटो में जगह नहीं होने के कारण वे अपनी लाइसेंसी बंदूक कंधे पर टांगकर पैदल प्रतापपुर नाका की ओर जा रहे थे। नवापारा-कुम्हारपारा ढलान के पास एक व्यक्ति ने पीछे से आकर बातचीत की और मोटरसाइकिल पर छोड़ने की बात कही। जैसे ही प्रार्थी बैठने लगा, आरोपी बंदूक लूटकर मौके से फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 72/26 के तहत मामला दर्ज किया गया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर साइबर सेल, कोतवाली और गांधीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की।

तकनीकी और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को कसाबेल से हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम जयपाल लकड़ा (45 वर्ष), निवासी महादेवडांड बीसबहरी, थाना बगीचा जिला जशपुर बताया।

आरोपी ने बंदूक लूट की घटना स्वीकार की, जिसके बाद उसके कब्जे से बंदूक बरामद कर ली गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है।

बीच सड़क अवैध बोरिंग के मामले में कोतवाली में ज्ञापन सौंपा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहर के मध्य सार्वजनिक सड़क पर कथित अवैध निजी बोरवेल खुदाई के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधियों ने थाना कोतवाली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र बहादुर सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता सुजान बिंद एवं अंकुर सिंहा ने थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम क्षेत्र की सार्वजनिक सड़क और शासकीय भूमि पर बिना अनुमति निजी बोरिंग कराई गई, जिससे यातायात बाधित हुआ और आम नागरिकों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हुआ। प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि जनदबाव के बाद ही खुदाई को पाटने की कार्रवाई शुरू की गई। उन्होंने मांग की कि बोरवेल मशीन जब्त कर संबंधित ठेकेदार, मशीन संचालक और कथित रूप से संलिप्त जनप्रतिनिधि के खिलाफ निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की जाए।

इंजीनियरिंग कॉलेज में नए तकनीकी व प्रबंधन पाठ्यक्रमों को एआईसीटीई की मंजूरी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली ने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 से नए तकनीकी एवं प्रबंधन पाठ्यक्रमों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। यह पहल सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज के प्रयासों से संभव हुई है। कॉलेज में अब एमबीए (30 सीटें) प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही कार्यरत कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बीटेक (30 सीटें) और एमटेक (15 सीटें) पाठ्यक्रम भी स्वीकृत किए गए हैं। एमटेक में सिविल इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एवं कंट्रोल तथा माइनिंग इंजीनियरिंग विषय शामिल होंगे। वहीं बीटेक में सिविल, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग का संचालन निर्धारित क्षमता अनुसार किया जाएगा। इस निर्णय से सरगुजा अंचल में ही उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी व प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध होगी। बीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, सिंचाई विभाग और माइनिंग सेक्टर में कार्यरत कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के पास ही वर्किंग प्रोफेशनल शिक्षा का अवसर मिलेगा। कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राम नारायण खरे ने इस उपलब्धि पर सभी प्राध्यापकों व कर्मचारियों को बधाई दी है।

महिला ने की आत्महत्या..अस्पताल में मायके-ससुराल पक्ष में विवाद

पति पर मारपीट के आरोप, पुलिस ने मर्ग कायम कर शुरू की जांच

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

गांधीनगर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद अस्पताल में मायके और ससुराल पक्ष के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मायके पक्ष ने मृतका के पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार फूलकुमारी चौधरी (37 वर्ष), पति गिरधर चौधरी, मूल रूप से लटोरी थाना क्षेत्र के द्वारिकानगर की रहने वाली थीं। वह पति और बच्चों के साथ गांधीनगर थाना क्षेत्र के फुंदूरडिहारी में निवासरत थीं। सोमवार को उनके बड़े बेटे का जन्मदिन था। बताया जा रहा है कि बेटे को नहाने के लिए डांटने के दौरान पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। गुस्से में महिला ने कुकर पति की ओर फेंक दिया और घर से बाहर चली गई। कुछ देर बाद वह बाथरूम में फांसी पर लटकी मिली। परिजन तत्काल उसे उतारकर निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया।

पिता ने लगाए गंभीर आरोप

पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में मायके और ससुराल पक्ष के लोग आमने-सामने हो गए। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि गिरधर चौधरी अक्सर उसकी बेटी के साथ मारपीट करता था। उनका कहना है कि घटना के दिन भी विवाद के दौरान मारपीट हुई थी।

पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर लिया है और आत्महत्या के कारणों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस लाइन में तैनात आरक्षक की रहस्यमयी मौत से हड़कंप

-संवाददाता-
सूरजपुर, 10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसने पूरे पुलिस महकमे को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। विश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजपुर पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिस आरक्षक अन्तोष खलखो (32) ने सोमवार देर रात अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। न कोई सुसाइड नोट, न कोई आखिरी संदेश–बस पीछे रह गया एक गहरा सन्नाटा और कई अनुत्तरित सवाल। मिली जानकारी के अनुसार, आरक्षक अन्तोष खलखो सोमवार को एमसीबी जिले में पुलिस ड्यूटी पूरी कर देर रात अपने घर लौटे थे। परिवार एसईसीएल कॉलोनी स्थित क्वार्टर में निवास करता है। रोज़मर्रा की तरह उन्होंने पड़ोस में स्थित ससुराल में परिवार के साथ भोजन किया और इसके बाद अपने क्वार्टर लौट आए। उस समय किसी तरह की असामान्य बात सामने नहीं आई थी। रात के कुछ समय बाद जब उनकी पत्नी दोनों बच्चों के साथ घर पहुंचीं, तो अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। आरक्षक फंदे से लटके हुए मिले। घबराए परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और उन्हें फंदे से

उतारकर नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही विश्रामपुर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। परिजन भी फिलहाल आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

20 मार्च को धूमधाम से मनाई जाएगी झूलेलाल जयंती

चेट्रीचंड़ महोत्सव के तहत सात दिवसीय कार्यक्रम होंगे आयोजित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

पूज्य सिंधी समाज अंबिकापुर द्वारा 20 मार्च 2026 को भगवान श्री झूलेलाल जयंती को 'चेट्रीचंड़ महोत्सव 2026' के रूप में भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर सात दिवसीय धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्थानीय सिंधु भवन में आयोजित बैठक में सिंधी समाज, महिला मंडल, वरिष्ठजन एवं युवाओं की उपस्थिति में कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। साथ ही सिंधी नवयुवक मंडल की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। नवयुवक मंडल के अध्यक्ष नितिन रेलवानी, उपाध्यक्ष हरिश आहूजा व हरिश वाटवानी,सचिव शुभम राजपाल तथा कोषाध्यक्ष यश नागदेव को बनाया गया है। महोत्सव के दौरान सिंधी प्रीमियर लीग क्रिकेट मैच,आनंद मेला, दीप प्रज्वलन,स्कूटर रैली,बच्चों की प्रतियोगिताएं,मेधावी छात्रों का सम्मान, शंकरघाट सफाई अभियान तथा विशाल लंगर का आयोजन होगा। 20 मार्च को शाम भव्य शोभायात्रा और ज्योति विसर्जन किया जाएगा। झूलेलाल जयंती 20 मार्च को चेट्रीचंड़ महोत्सव के रूप में मनाई जाएगी। सात दिनों तक विभिन्न सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम होंगे।

फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन अभियान का हुआ शुभारंभ

शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवापारा में जनप्रतिनिधियों ने स्वयं दवा का सेवन कर लोगों को दवा सेवन करने अपील की

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा में मंगलवार को राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव,नगर निगम अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजूषा भगत,स्थानीय जनप्रतिनिधि,शहरी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. शीला नेताम,शहरी सुपरवाइजर अनिल कुमार पांडे,धनेश प्रताप सिंह सहित अस्पताल के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाएं एल्बेंडाजोल,डी.ई.सी. एवं इवरमेक्टिन का सेवन कर लोगों को दवा सेवन करने प्रोत्साहित किया। इस दौरान उपस्थित लोगों को फाइलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से बचाव हेतु दवा सेवन के महत्व के बारे में जानकारी दी गई एवं दवा सेवन करने अपील की गई।

इस अभियान के अंतर्गत शहरी क्षेत्र अंबिकापुर में कुल 300 टीमों का गठन किया गया है, जिनके द्वारा सभी आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों में बूथ स्थापित कर दवा वितरण किया जा रहा है। बता दें अभियान अंतर्गत 10, 11 एवं 12 फरवरी 2026 को बूथों के माध्यम से दवा सेवन कराया जाएगा। 13 फरवरी से 23 फरवरी 2026 तक दवा प्रशासकों द्वारा घर-घर जाकर दवा खिलाई जाएगी। वहीं 24 एवं 25 फरवरी 2026 को छूटे हुए पात्र व्यक्तियों को दवा सेवन कराया जाएगा।

जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का गांधी स्टेडियम में हुआ भव्य शुभारंभ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने एवं युवाओं में खेल भावना के विकास के उद्देश्य से गांधी स्टेडियम, अम्बिकापुर में आज जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक का भव्य शुभारंभ किया गया। यह प्रतियोगिता 10 से 12 फरवरी 2026 तक आयोजित की जा रही है, जिसमें जिले के सभी विकासखंडों से आए खिलाड़ी उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर मंजूषा भगत उपस्थित रहीं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर निगम सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ पार्षद आलोक दुबे,शैलेश कुमार सिंह,रविकांत उरांव,अनिल मेजर सिंह, भारत सिंह सिसौदिया,कलेक्टर

अजीत वसंत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी,जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में खेल प्रतिभागी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि महापौर मंजूषा भगत ने कहा कि बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर आयोजित सरगुजा ओलंपिक ग्रामीण क्षेत्रों की छिपी खेल प्रतिभाओं को निखारने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है,जो शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ रखता है। महापौर ने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाई

और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएँ दीं। सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने अपने संबोधन में कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास,टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना बनाए रखते हुए प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। अतिथियों द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी आगे संभाग स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन,समर्पण और खेल भावना के साथ भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि जिला प्रशासन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगा। जिला स्तरीय सरगुजा ओलंपिक में जिले के सभी विकासखंडों सीतापुर,बतौली,लखनपुर,उदयपुर,लूण्ड्रा, मैनपाट और अम्बिकापुर से आए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। प्रतियोगिता में 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाएँ तथा 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला एवं पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 12 विभिन्न खेल विधाओं में प्रतियोगिताएँ आयोजित की जा रही हैं, जिनमें एथलेटिक्स सहित अन्य प्रमुख खेल शामिल हैं।

सुरजपुर कांग्रेस की कार्यकारिणी या पदों का महाकुंभ?

अध्यक्ष-कोषाध्यक्ष छोड़ बाकी पर लंबी कतार

एक अध्यक्ष, एक कोषाध्यक्ष...बाकी पदों पर भीड़-नई सूची ने बढ़ाई सियासी हलचल

- तुम भी खुश,हम भी खुश फॉर्मूला! सुरजपुर कांग्रेस में पदों की बारिश
- 51 सचिव,37 संयुक्त सचिव...संगठन विस्तार या रेवड़ी वितरण?
- पदाधिकारियों की फौज तैयार-सुरजपुर कांग्रेस में जिम्मेदारी कम,पद ज्यादा?
- कार्यकारिणी कम,नामों की परेड ज्यादा-नई सूची पर उठे सवाल...
- रेवड़ी मॉडल पर बनी टीम? कांग्रेस की नई कार्यकारिणी चर्चा में...
- उद्योगपति बने कोषाध्यक्ष,क्या चुनावी तैयारी का संकेत?
- नई टीम,नई रणनीति-संगठन मजबूत या आर्थिक गणित?

- 51 सचिव, 37 संयुक्त सचिव, 24 स्थायी और 28 विशेष आमंत्रित सदस्य... नामों की बाढ़ जैसी सूची के चर्चे
- कोषाध्यक्ष पद पर उद्योगपति...तुम भी खुश, हम भी खुश' फॉर्मूला ही चला क्या?

-न्यूज डेस्क-

सुरजपुर,10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी सुरजपुर की अनुमोदित कार्यकारिणी की सूची जारी होते ही जिले की सियासत में हलचल तेज हो गई है। चार पन्नों में फैली इस लंबी सूची को देखकर राजनीतिक गलियारों में व्यंग्य भी चल रहा है और चर्चा भी – क्योंकि अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जैसे दो अहम पदों को छोड़ दिया जाए तो बाकी लगभग हर स्तर पर पदाधिकारियों की लंबी कतार नजर आ रही है। कई कार्यकर्ता इसे संगठन विस्तार बता रहे हैं, तो कई इसे'तुम भी खुश, हम भी खुश' फॉर्मूले का नतीजा कह रहे हैं,सुरजपुर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी ने जिले की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। किसी के लिए यह संगठन विस्तार का बड़ा कदम है,तो किसी के लिए'पदों का महाकुंभ '। फिलहाल इतना तय है कि सूची ने सबको चर्चा का मौका जरूर दे दिया है–अब देखना यह है कि यह टीम मैदान में कितनी सक्रिय रहती है या फिर पदों की भीड़ में संगठन की दिशा कहीं खो न जाए।

पद इतने कि संगठन छोटा,सूची बड़ी लगने लगी

जारी सूची में जिलाध्यक्ष के रूप में सुश्री शशि सिंह का नाम शीर्ष पर है,कोषाध्यक्ष की नियुक्ति भी एकल है,लेकिन इसके बाद जैसे ही पदों का सिलसिला शुरू होता है,आंकड़ा तेजी से बढ़ता जाता है,उपाध्यक्ष,महामंत्री,मीडिया प्रभारी,प्रवक्ता से लेकर संयुक्त महामंत्री और सचिव तक–हर पद पर संख्या इतनी बढ़ी कि कार्यकारिणी कम और पदाधिकारियों की फेहरिस्त ज्यादा दिखाई देने लगी, सबसे ज्यादा चर्चा सचिव पद को लेकर है,जहां 51 नाम शामिल किए गए हैं। वहीं संयुक्त सचिवों की संख्या 37 तक पहुंच गई है,स्थायी और विशेष आमंत्रित सदस्यों की सूची भी किसी मिनी सम्मेलन से कम नहीं दिख रही। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इतनी बड़ी टीम बनाकर पार्टी ने शायद यह सुनिश्चित कर लिया है कि'कोई नाराज न रहे',भले ही जिम्मेदारियों का गणित बाद में तय करना पड़े।

'रेवड़ी मॉडल' या संगठन विस्तार?

सूची सामने आते ही विरोधी दलों के साथ-साथ कांग्रेस के अंदर भी हल्की-फुल्की चुटकी शुरू हो गई। कुछ नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह कार्यकारिणी कम और'रेवड़ी वितरण योजना' ज्यादा लग रही है, व्यंग्य में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कहा...'पहले संगठन में जगह पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी,अब सूची इतनी लंबी है कि मेहनत कम और संतुलन ज्यादा दिखता है।'हालांकि पार्टी के समर्थक इसे सकारात्मक कदम बताते हुए कहते हैं कि ज्यादा लोगों को जिम्मेदारी देने से संगठन जमीनी स्तर तक मजबूत होगा और चुनावी तैयारियों को गति मिलेगी।

सचिवों की फौज,कार्यकारिणी सदस्य पीछे : दिलचस्प पहलू यह भी है कि सचिव और संयुक्त सचिव पदों पर नियुक्तियां कार्यकारिणी सदस्यों से कई गुना ज्यादा हैं। इससे संगठनात्मक संरचना को लेकर सवाल उठ रहे हैं, राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जब पद ज्यादा और अधिकार कम हों,तो संगठन में जिम्मेदारी का स्पष्ट बंटवारा करना चुनौती बन जाता है, कुछ लोग मजाक में कह रहे हैं–'अब बैठक में कुर्सियां कम पड़ेंगी या माइक्रोफोन? '

कोषाध्यक्ष की नियुक्ति पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म : नई कार्यकारिणी में कोषाध्यक्ष पद पर उद्योगपति वर्ग से जुड़े व्यक्ति की नियुक्ति ने अलग ही बहस छेड़ दी है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि क्या आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी आर्थिक रूप से मजबूत चेहरा सामने लाना चाहती है, व्यंग्य में कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि–'दौड़-भाग की जिम्मेदारी बाकी पदाधिकारियों की, और फंड की जिम्मेदारी उद्योगपति के पास।' हालांकि पार्टी के करीबी लोग इसे वित्तीय प्रबंधन मजबूत करने की रणनीति बता रहे हैं।

संख्या इतनी कि कार्यकारिणी कम,सूची ज्यादा लगे...

- उपाध्यक्ष पद पर दर्जनभर नाम,
- महामंत्री और मीडिया प्रभारी में भी एक से अधिक नियुक्तियां,
- संयुक्त महामंत्री की लंबी सूची,
- सचिव पद पर तो मानो रिकॉर्ड बना दिया गया हो – 51 नाम,
- संयुक्त सचिव 37,
- स्थायी आमंत्रित सदस्य 24 और विशेष आमंत्रित सदस्य 28 तक पहुंच गए।

वरिष्ठता का गणित बना पहेली

इतनी बड़ी सूची जारी होने के बाद कई नए पदाधिकारी इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि वरिष्ठता का पैमाना क्या होगा,सूची में नाम के क्रम से वरिष्ठता तय होगी या सभी को समान दर्जा मिलेगा–इस पर अभी स्पष्टता नहीं है, संगठन के पुराने नेताओं का कहना है कि जब पद ज्यादा और पदाधिकारी ज्यादा हों, तो सबसे बड़ी चुनौती तालमेल बनाए रखना होती है।

राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कार्यकारिणी केवल संगठन विस्तार नहीं,बल्कि अंदरूनी गुटबाजी और असंतोष को संतुलित करने की रणनीति भी हो सकती है,जिले में लंबे समय से चल रही खींचतान को देखते हुए पार्टी ने शायद ज्यादा से ज्यादा चेहरों को शामिल कर'सबको साथ' रखने का संदेश देने की कोशिश की है,लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इतनी बड़ी टीम मैदान में उतनी ही सक्रिय दिखाई देगी,या फिर सूची केवल कागजों में ही चमकती रह जाएगी।

आगे की राहः जिम्मेदारी या सिर्फ पद?

अब असली परीक्षा तब होगी जब संगठनात्मक कार्यक्रम शुरू होंगे और देखा जाएगा कि इतने पदाधिकारी जमीन पर कितना सक्रिय रहते हैं, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर हर पदाधिकारी वास्तव में जिम्मेदारी निभाता है तो संगठन मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर पद केवल नाम तक सीमित रहे तो यह सूची व्यंग्य का विषय बनती रहेगी।

वाड्राफनगर जनपद के पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी आया पुलिस के गिरफ्त में

30 लाख रूपये का फर्जीवाड़ा कर हुआ था फरार

-संवाददाता-
वाड्राफनगर,10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद पंचायत वाइफनगर क्षेत्र के ग्रामों में मुरुम मिट्टी, सडक व अन्य निर्माण का फर्जी बिल लगाकर,कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर करीब 30 लाख से अधिक की रकम का फर्जीवाड़ा कर कई वर्षों से फरार फरार चल रहा था, पुलिस ने आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाइफनगर को गिरफ्तार कर भेजा गया सलाखों के पीछे, पुलिस चौकी वाइफनगर,थाना बसंतपुर,जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) ने भगोड़ा आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी को गिरफ्तार कर

अपराध क्रमांक 50/2020, धारा 467, 468, 409. 420. 34 ता. हि के तहत तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड्रफनगर श्रवण कुमार मरकाम उर्फ एस0 के0 मरकाम पिता स्व. बिकाउ राम मरकाम,उम्र 62 वर्ष,साकिन शिवमंदीर, महुआपारा वार्ड क्रमांक 04,थाना गांधीनगर, अंबिकापुर को भेजा सलाखों के पीछे। जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत तुगंवा, गुडरू,जमई,पेण्डारी में मुरम मिट्टी,सड़क व सह पुलिया, तटबंध,डब्लूबीएम निर्माण का फर्जी बिल लगाकर वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासकीय राशि का हेराफेरी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर गबन करने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड्रफनगर द्वारा पत्र क्रमांक-1825/मनरेगा/स्था/ज0पं0/2020-21 वाड्रफनगर दिनांक 30/04/2020 के माध्यम से जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेज पेश करने पर थाना बसंतपुर चौकी वाड्रफनगर में आरोपी अश्विनी कुमार तिवारी कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) जनपद पंचायत वाड्रफनगर के विरूद्ध वर्ष 2020 में अपराध क्रमांक 50/2020 बारा 467,468,420,409, 34 ता.हि. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना दौरान पूर्व में प्रकरण के आरोपी अश्विनी कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। प्रकरण में विवेचना दौरान मामले के अन्य आरोपी सप्लायर हरिहर यादव,कुजलाल साहू व रोजगार सहायक गिरीश यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। वर्तमान में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर के द्वारा प्रकरण में जनपद पंचायत के कर्मचारियों व सप्लायर का माननीय न्यायालय से धारा 164 जा0 फौ0 का कथन कराकर प्रकरण के गिर0 आरोपियों के विरुद्ध माननीय व्यायालय में पूरक चालान तैयार कर पेश किया गया है। प्रकरण के विवेचना के कम में आरोपी अश्विनी कुमार तिवारी के द्वारा अपने कथन में यह बताया गया है कि उसने एस. के. मरकाम व एक अन्य के साथ मिलकर शासकीय राशि 30,02,449 रु. का गबन किया गया है, प्रकरण में कई वर्षों से फरार आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड्रफनगर श्रवण कुमार मरकाम उर्फ एस0 के0 मरकाम पिता स्व. बिकाउ राम मरकाम उम्र 62 वर्ष साकिन शिवमंदीर महुआपारा वार्ड क्रमांक 04 थाना गांधीनगर अंबिकापुर को हिरासत में लेकर वाड्रफनगर लाया गया जिससे पूछताछ के दौरान अपना आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वाड्रफनगर श्रवण कुमार मरकाम उर्फ एस0 के0 मरकाम पिता स्व. बिकाउ राम मरकाम उम्र 62 वर्ष साकिन शिवमंदीर महुआपारा वार्ड क्रमांक 04 थाना गांधीनगर अंबिकापुर विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। मामले में फरार अन्य आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत अम्बिकापुर में 260 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्पन्न

वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवदंपतियों को दिया आशीर्वाद

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज जिला मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित पीजी कॉलेज के हॉकी मैदान में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सामाजिक समरसता, परंपरा और सादगी का अद्भुत संगम बने इस आयोजन में कुल 260 नवविवाहित जोड़ों का विधि-विधान से विवाह सम्पन्न कराया गया। कार्यक्रम में गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर महापौर मंजूषा भगत,नगर निगम सभापतिहरिमन्दर सिंह टिन्नी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में परिजन शामिल हुए । अतिथियों ने नवदम्पतियों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखद,समृद्ध एवं सफल वैवाहिक जीवन की कामना की।

विविध परंपराओं के अनुसार सम्पन्न हुआ विवाह : सामूहिक विवाह समारोह में सामाजिक सौहार्द्र की सुंदर मिसाल देखने को मिली। कुल 260 जोड़ों में से192 जोड़ों का विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक विधि-विधान से सम्पन्न कराया गया,वहीं 68 जोड़ों का विवाह ईसाई परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। दोनों ही प्रक्रिया के लिए पृथक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थीं,जिससे सभी समुदायों की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान किया जा सके।

राज्यव्यापी आयोजन का हिस्सा : यह सामूहिक विवाह समारोह प्रदेश स्तर पर एक साथ आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा था। रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े द्वारा वर्चुअल माध्यम से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान किया गया। अम्बिकापुर में आयोजित कार्यक्रम में भी इस अवसर का सीधा प्रसारण किया गया, जिससे नवदम्पति एवं उनके परिजन भावनात्मक रूप से राज्य स्तरीय आयोजन से जुड़े रहे।

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सहारा

जिला कार्यक्रम अधिकारी,महिला एवं बाल विकास विभाग,जे.आर. प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2005 से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं जरूरतमंद परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं के विवाह में सहयोग प्रदान करना है, ताकि आर्थिक अभाव विवाह में बाधा न बने। उन्होंने बताया कि योजना के प्रारंभ से अब तक सरगुजा जिले में 9,890 जोड़ों का विवाह इस योजना के माध्यम से सम्पन्न कराया जा चुका है। आज आयोजित समारोह में 260 जोड़ों को वैवाहिक बंधन में बंधने का अवसर मिला।

समारोह की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं

कार्यक्रम स्थल पर वर-वधुओं एवं उनके परिजनों के लिए बैठक,भोजन,पेयजल, चिकित्सा,पंजीयन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई थी। विवाह संस्कारों के सुचारु संचालन हेतु पंडितों, पादरियों एवं सहयोगी दलों की तैनाती की गई थी। सुरक्षा, पार्किंग एवं यातायात व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रही।

सामाजिक एकता का संदेश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह न केवल जरूरतमंद परिवारों के लिए आर्थिक सहयोग का माध्यम बना, बल्कि समाज में सादगीपूर्ण विवाह, सामूहिक सहभागिता और सामाजिक एकता का भी संदेश दिया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भर्ती प्रक्रिया की लेट लतीफी से अभ्यर्थी परेशान

-संवाददाता-
लखनपुर,10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया कई महीनों से लंबित पड़ी हुई है, जिससे सैकड़ों अभ्यर्थी परेशान हैं। जुलाई 2025 में लखनपुर ब्लॉक के परियोजना कार्यालय में कार्यकर्ता व सहायिका कुल 22 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिनमें कार्यकर्ता के 5 व 17 सहायिका के रिक्त पद थे जिसमें लगभग 350 फॉर्म विभिन्न ग्राम पंचायतों के उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए थे,आज सात महीने बीत जाने के बावजूद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। अभ्यर्थियों के बार-बार पूछने पर परियोजना कार्यालय से बताया जाता है कि मूल्यांकन समिति ने अभी तक स्थाई समिति का गठन नहीं किया है,जिसके कारण पूरा मामला अटका हुआ है। इस देरी से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्रों पर कार्यकर्ता और सहायिका की कमी बनी हुई है, जिसका सीधा असर बच्चों की देखभाल,पोषण और शिक्षा पर पड़ रहा है। अभ्यर्थी बताते हैं कि वे लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और बार-बार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं,लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही। स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, और उम्मीद है कि जल्द ही स्थाई समिति गठित होकर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। संबंधित विभाग से उम्मीदवारों की मांग है कि इस लंबित प्रक्रिया को प्राथमिकता देकर जल्द पूरा किया जाए ताकि योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल सके और आंगनवाड़ी केंद्र सुचारू रूप से चल सकें। इस संबंध में जिला परियोजना अधिकारी जे आर प्रधान ने बताया कि जितने भी आवेदन आए हुए हैं मूल्यांकन समिति के द्वारा अंक सूची का सत्यापन किया जा रहा है जिससे थोड़ा सा विलंब हो रहा है आगामी एक महीना के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

स्व. देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव की छठवी पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 फरवरी 2026
(घटती-घटना)।

स्व देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव की छठवी पुण्यतिथि पर मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजीव भवन में श्रद्धांजली दी गई। इस दौरान उनके ज्येष्ठ पुत्र पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव भी उपस्थित थे। स्व. देवेंद्र कुमारी सिंह देव अंबिकापुर व बैकुंठपुर से विधायक भी रहीं। राजीव भवन में श्रद्धांजलि उपरांत प्रतीक्षा बस स्टैण्ड चौक पर पूर्व महाराज स्व. एमएस सिंहदेव एवं स्व देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव के युगल प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके उपरांत मां महामाया मंदिर में आयोजित भंडारे में पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रसाद का वितरण किया। इस दौरान डॉ. प्रेमसाय सिंह,अजय अग्रवाल,जेपी श्रीवास्तव,डॉ. अजय तिर्की,राकेश गुप्ता,हेमंत सिन्हा,मो इस्लाम,विनय शर्मा,इंद्रजीत सिंह धंजल,सत्येन्द्र तिवारी,जगन्नाथ कुशवाहा सहित अन्य मौजूद थे।

CMYK

आग में जली ट्रक ने खोली पोल

प्रतिबंधित थाई मांगुर की सप्लाई पर सिस्टम खामोश क्यों?

बैन मछली का 'ब्लाइंड ट्रांजिट': उड़ीसा से एमपी तक पहुंची खेप, जांच पर बड़े सवाल

प्रतिबंध कागजों में, सड़क पर कारोबार – आग लगी तो खुला मांगुर तस्करी का राज

-रवि सिंह-

कोरिया,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

कभी-कभी एक हादसा सिर्फ दुर्घटना नहीं होता,बल्कि उस सिस्टम का आईना बन जाता है जो कागजों में सख्त और जमीन पर ढीला नजर आता है,पटना थाना क्षेत्र के रनई के पास उड़ीसा से मध्यप्रदेश की ओर जा रही एक ट्रक में लगी आग ने भी कुछ ऐसा ही किया,ट्रक जलने के बाद सड़क पर पानी में तैरती हजारों मछलियों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया–जब थाई मांगुर मछली पूरे देश में प्रतिबंधित है, तो यह इतनी आसानी से राज्यों की सीमाएं पार कैसे कर रही थी? अगर यह ट्रक नहीं जलता, तो शायद यह खेप भी बिना किसी शोर-शराबे के अपने गंतव्य कटनी पहुंच जाती और सिस्टम को भनक तक नहीं लगती।

जांच चौकियां या सिर्फ औपचारिकता?

जानकारी के मुताबिक यह ट्रक उड़ीसा से चला और जशपुर,सरगुजा,सूरजपुर होते हुए कोरिया जिले तक पहुंच गया,इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद कहीं कोई जांच नहीं हुई–न मत्स्य विभाग की नजर पड़ी, न परिवहन जांच की सख्ती दिखी और न ही स्थानीय प्रशासन ने कोई संदेह जताया, यही वह बिंदु है जहां सवालों की कतार शुरू होती है,क्या प्रतिबंधित सामग्री की पहचान करना किसी की जिम्मेदारी नहीं रही? क्या जांच चौकियां सिर्फ कागजों पर ही सक्रिय हैं? या फिर अवैध सप्लाई करने वालों को पहले से पता रहता है कि कहां रोक नहीं लगेगी? यह घटना साफ संकेत देती है कि अवैध नेटवर्क सिर्फ सक्रिय ही नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरियों को समझकर काम कर रहा है।

प्रतिबंधित मछली का खुला खेल

थाई मांगुर मछली को वर्षों पहले पर्यावरण और स्वास्थ्य कारणों से प्रतिबंधित किया गया था, इसके बावजूद यह मछली चोरी-छिपे पाली जा रही है और ट्रकों में भरकर एक राज्य से दूसरे राज्य तक भेजी जा रही है, स्थानीय लोगों के अनुसार,आग बुझने के बाद जब ट्रक का पिछला हिस्सा खुला तो पानी के साथ बड़ी संख्या में मछलियां बाहर निकलने लगीं। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ लग गई और लोग मछलियां पकड़कर घर ले जाते रहे,नियमों के अनुसार ऐसी स्थिति में–पूरी खेप को जब्त करना चाहिए था, मछलियों को गड्ढा खोदकर नष्ट करना चाहिए था,और परिवहनकर्ता पर तत्काल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन मौके पर यह सख्ती दिखाई नहीं दी,उल्टा,चर्चा यह भी रही कि ट्रक मालिक दूसरी गाड़ी बुलाकर बची हुई मछलियों को आगे भेजने की कोशिश कर रहा था।

जिम्मेदारी किसकी?

इस पूरे मामले में कई विभागों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं परिवहन जांच व्यवस्था,मत्स्य विभाग की निगरानी,स्थानीय पुलिस की सतर्कता, और प्रशासनिक समन्वय,जब एक प्रतिबंधित वस्तु इतने लंबे रास्ते से गुजरकर गंतव्य के करीब पहुंच जाए,तो यह सिर्फ एक विभाग की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की विफलता मानी जाती है।

मुनाफे का गणित और कानून की हार

थाई मांगुर के अवैध कारोबार की सबसे बड़ी वजह उसका तेज उत्पादन और भारी मुनाफा है, कम समय में तेजी से वजन बढ़ता है,पालन सस्ता पड़ता है,बाजार में अच्छी कीमत मिल जाती है,यानी जोखिम ज्यादा है, लेकिन मुनाफा उससे भी ज्यादा, यही वजह है कि तस्कर कानून की परवाह किए बिना इसे राज्यों के बीच भेज रहे हैं,कहा जाता है कि अवैध व्यापार वहीं फलता-फूलता है जहां निगरानी कमजोर हो–और यह घटना उसी सिद्धांत को साबित करती नजर आती है।

हादसा नहीं होता तो क्या खुलता सच?

यह सवाल सबसे अहम है–अगर ट्रक में आग नहीं लगती तो क्या प्रशासन को कभी पता चलता कि प्रतिबंधित मछली इतनी आसानी से जिले की सीमा तक पहुंच चुकी है? संभवतः नहीं,यही वजह है कि इस घटना को लोग दुर्घटना से ज्यादा खुलासा मान रहे हैं, क्योंकि यहां पकड़ा गया नेटवर्क शायद उस बड़े अवैध सिस्टम की सिर्फ एक झलक भर हो सकता है।

सिस्टम सोया या सुलाया गया?

रनई की घटना एक चेतावनी है,यह बताती है कि कानून बनाने भर से समस्या खत्म नहीं होती, उसे जमीन पर लागू करना भी उतना ही जरूरी है,आज सवाल सिर्फ एक ट्रक या कुछ हजार मछलियों का नहीं है,सवाल यह है कि अगर हादसा नहीं होता,तो शायद यह 'प्रतिबंधित सफर' भी सिस्टम की आंखों से बचकर चुपचाप पूरा हो जाता।

पर्यावरण और स्वास्थ्य पर खतरा...

विशेषज्ञ बताते हैं कि थाई मांगुर मछली किसी भी तरह के पानी में जीवित रह सकती है और स्थानीय मछलियों के लिए खतरा बनती है,गंदे वातावरण में पाली जाने के कारण इसके जरिए संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है,इसी वजह से इसे प्रतिबंधित किया गया था ताकि न केवल पर्यावरण सुरक्षित रहे, बल्कि लोगों की सेहत पर भी असर न पड़े, लेकिन जब ऐसी मछली खुलेआम सड़कों पर घूमती दिखाई दे, तो यह सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा भी बन जाता है।

कानून सख्त,अमल ढीला...

देश में थाई मांगुर मछली के पालन,बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध कोई नई बात नहीं है मत्स्य विभाग और पर्यावरण एजेंसियों को समय-समय पर निर्देश दिए जाते रहे हैं कि कहीं भी इस मछली का उत्पादन या भंडारण मिले तो उसे तुरंत नष्ट किया जाए,लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है, रनई की घटना यह बताती है कि प्रतिबंध कागजों में भले सख्त हो,लेकिन जमीन पर उसका पालन ढीला नजर आता है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 189 जोड़ों का सामूहिक विवाह

विधायक श्याम बिहारी जायसवाल रहे मुख्य अतिथि

-संवाददाता-

खड़गवां,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत खड़गवां क्षेत्र के चनवारीडांड स्थित मां महामाया धाम में 189 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ। धार्मिक और उत्सवी वातावरण में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में परिजन,बाराती और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल उपस्थित रहे। उनके साथ अनुविभागीय अधिकारी,स्थानीय सरपंच,महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी-कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

कार्यक्रम के दौरान सभी वर-वधु जोड़ों का पारंपरिक रीति-रिवाजों से विवाह संपन्न कराया गया। विभाग की ओर से प्रत्येक नवदंपति को ?35,000 की प्रोत्साहन राशि का चेक तथा लगभग ?15,000 का श्रृंगार एवं गृहस्थी सामग्री उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि राज्य सरकार बेटियों के हित में निरंतर अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष योजना में विवाह के लिए किसी प्रकार की संख्या सीमा निर्धारित नहीं की गई है। जिन पात्र बेटा-बेटियों को विवाह करना है, वे महिला एवं बाल विकास विभाग से संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं। विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह आयोजित किए जा रहे हैं। विधायक जायसवाल ने अपने संबोधन में नवदंपतियों और उपस्थित लोगों से सड़क सुरक्षा को लेकर भी अपील की। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि द्वारा कई नवविवाहित जोड़ों को मंच पर चेक और उपहार सामग्री प्रदान कर उनके सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी गईं। समारोह का सफल संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया।

आगामी कार्ययोजना को लेकर भाजपा बूथ प्रभारियों की बैठक,संगठन मजबूती पर बना रोडमैप

छिंदडांड़ जिला कार्यालय में हुई बैठक, बूथ स्तर तक योजनाओं को पहुंचाने पर जोर

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया द्वारा आगामी कार्ययोजना को लेकर बूथ स्तरीय प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक भाजपा जिला कार्यालय छिंदडांड़ में आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पं. दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। बैठक में संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण और जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी, पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल, सहकारी बैंक सरगुजा उपाध्यक्ष जगदीश साहू, जिला उपाध्यक्ष बसंत राय,अशोक जायसवाल, राजेश सिंह,चुन्नी पैकरा,अनिल साहू,जनपद उपाध्यक्ष प्यारे साहू, जिला महामंत्री पंकज गुप्ता, कपिल जायसवाल सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

जिलाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र

और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति तक पहुंचाना पार्टी की प्राथमिकता है। उन्होंने बूथ प्रभारियों से आह्वान किया कि वे बूथ स्तर पर प्रवास कर समितियों का सत्यापन करें और संगठन की संरचना को और मजबूत बनाएं। पूर्व जिलाध्यक्ष कृष्णबिहारी जायसवाल ने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत रोजगार गारंटी जैसी योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और श्रमिक वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त होगा। बैठक में जिला सह मीडिया प्रभारी गणेश यादव, सोशल मीडिया प्रभारी जगनारायण साहू, मंडल अध्यक्ष अनिल खटिक, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सतेन्द्र राजवाड़े, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवचरण साहू सहित बड़ी संख्या में बूथ प्रभारी और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन विस्तार और आगामी अभियानों को लेकर विस्तृत कार्ययोजना पर सहमति बनी।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैयाथान, जिला सूरजपुर,छ0ग0

रा0प्र0क्र0 /अ-2/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम ग्रामीण जन ग्राम पंचायत बैजनाथनगर नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद जिला सूरजपुर को सूचित किया जाता है कि श्री बिरेन्द्र कुमार पिता गोरेलाल निवासी बैजनाथनगर के द्वारा अपने स्वत्व एवं अधिपत्य की भूमि खसरा नं0 1449/5 रकबा 0.19 हे0 में से 0.04 हे0 जो ग्राम बैजनाथनगर प.ह.नं 22 रा0नि0मं0 सलका तहसील भटगांव जिला सूरजपुर में स्थित है के आवासीय भू परिवर्तन (डायवर्सन) हेतु इस न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त संबंध में ग्राम पंचायत/नगर पंचायत/नगर पालिका निगम क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा किसी विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रकरण में नियत दिनांक 16.02/2026 को न्यायालयीन समयावधि में उपस्थित होकर दावा / आपत्ति पेश कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 02/021026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायलय की मुद्रा से जारी किया गया है।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैयाथान,सूरजपुर

न्यायालय तहसीलदार रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज,छ0ग0

क्रमांक/177/वाचक/तह./2026
रामानुजगंज दिनांक-28/01/2026

ईश्तहार

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम-रामानुजगंज को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो0 अकबर आ0 कमरूद्दीन निवासी रामानुजगंज थाना व तहसील रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ0ग0) के द्वारा के पुत्री सानीया आफरीन के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

यदि उक्त जाच बिन्दु में वर्णित तथ्य के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से दिनांक-16/2/2026 को अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। उक्त नियत समयावधि के पश्चात प्रस्तुत दावा/आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा ।

आज दिनांक-28/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

सील — तहसीलदार रामानुजगंज जिला-बलरामपुर-रा.गंज

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.)अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा(छ0ग0)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. ...../अ-2/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक तारीक बदर सिद्दकी पिता बदरूद्दीन सिद्दीकी जाति मुसलमान निवासी नवागढ़ तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा अपने स्वामित्व एवं आंधिय की भूमि स्थित ग्राम मायापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ0ग0) खसरा नंबर 356/132 रकबा 0.032 हे0 भूमि को कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन कराने के लिए भूमि की बी 1 खसरा रजिस्ट्री की प्रति आदि संहित आवेदन प्रस्तुत किया है जो इस सायालय में विचाराधीन है ।

अतएव उक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित सुनवाई तिथि 17 /2 /2026 को मेरे न्यायालय में अथवा अधीक्षक भू-अभिलेख के कार्यालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 9/02/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा0प्र0क्र0/...../अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदकगण गुंजा बाई उर्फ गुड्डी बाई पुत्री हीराधन, कंजलसा भुईया उर्फ कंजान राम आ0 हीराधन, दोनों जाति भुईया, निवासी दर्रीपारा अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर 10 मोहल्ला दर्रीपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 3836 रकबा 0.04 एकड़ में से रकबा 0.01, 1/2 एकड़ भूमि को अनावेदक / केता चंद्रवती पासवान पत्नी छत्रपाल पासवान, जाति पासवान, निवासी दर्रीपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा छ0ग0 के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 18/02/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांकः- 03.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील — नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

CMYK

सीएम के रास्ते साफ, पर शिकायतों पर ताला

बैकुंठपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान

या दिखाओ अभियान?

जनदर्शन में सुनवाई,ज़मीन पर चुप्पी-पुराने बस स्टैंड का अतिक्रमण बना प्रशासन की परीक्षा

जहां वीआईपी नजर, वहां बुलडोज़र तेज...बाकी जगह नियम भी धूप में सूखते?

जनदर्शन या मुखदर्शन? खबरें छपीं,आवेदन हुए, फिर भी अतिक्रमण जस का तस...

चौड़ीकरण के नाम पर चयनात्मक कार्रवाई-बैकुंठपुर में नियमों की नई परिभाषा...

बुलडोज़र का जीपीएस ऑनः सीएम मार्ग चमका, बस स्टैंड फिर भी बचा!

फल धूप में सूखे या नियम? अतिक्रमण पर प्रशासन की मीठी चुप्पी

-रवि सिंह-

कोरिया,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले बैकुंठपुर शहर में अतिक्रमण हटाने की ऐसी तेज़ रफ्तार देखने को मिली, मानो वर्षों से सोई हुई व्यवस्था अचानक अलार्म बजते ही जाग गई हो, घड़ी चौक से लेकर खरबत चौक तक फुटपाथ, छोटे ठेले, बोर्ड और अस्थायी ढांचे हटाकर सड़क को चमका दिया गया, ताकि वीआईपी काफिले को कहीं असुविधा न हो, लेकिन इसी चमक के बीच पुराने बस स्टैंड का वह अतिक्रमण आज भी जस का तस खड़ा है, जिस पर वर्षों से शिकायतें हो रही हैं, खबरें छप रही हैं और जनदर्शन में आवेदन दिए जा रहे हैं, सवाल उठ रहा है कि

आखिर यह कार्रवाई नियमों के तहत हो रही है या फिर ÷जहां कैमरा, वहां कार्रवाई÷ वाला फार्मूला लागू है।

खबर छपी,जनदर्शन हुआ... लेकिन जमीन पर वही पुराना दृश्य

पूर्व में प्रकाशित खबर में पुराने बस स्टैंड की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को विस्तार से उजागर किया गया था,शिकायतकर्ता ने जनदर्शन में आवेदन देकर उम्मीद जताई थी कि अब शायद प्रशासन जागेगा और सार्वजनिक गैलरी आम लोगों के लिए खुल सकेगी। जनदर्शन में सुनवाई भी हुई,आश्वासन भी मिला,लेकिन महीनों बाद भी न तो गैलरी खाली हुई और न ही अतिक्रमण हटाने की कोई ठोस कार्रवाई नजर आई,अब स्थानीय लोग तंज कसते हुए कहते हैं कि जनदर्शन शायद समस्या सुनने का मंच कम और मुखदर्शन का कार्यक्रम ज्यादा बन गया है-जहां जनता अपनी समस्या सुनाती है और फाइलें सुनकर सो जाती हैं।

स्थानीय जनता की मांग और प्रशासन के लिए आईना

स्थानीय नागरिकों की मांग है कि सभी अतिक्रमणों पर समान नियम लागू हों, सार्वजनिक गैलरी और रास्ते आम लोगों के लिए मुक्त किए जाएं,जनदर्शन में दिए गए आवेदनों पर समयबद्ध कार्रवाई हो,और वीआईपी दौरे से पहले नहीं, बल्कि पूरे साल नियमों का पालन कराया जाए।

दिखावे की सफाई या व्यवस्था की सच्चाई?

बैकुंठपुर में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या प्रशासन का बुलडोज़र सिर्फ वीआईपी नजरों के लिए चलता है, या फिर यह शहर की स्थायी व्यवस्था सुधारने का प्रयास है, अभी हालात यह हैं कि मुख्यमंत्री के स्वागत में सड़कें जरूर चमक रही हैं, लेकिन जनदर्शन में की गई शिकायतों की फाइलें शायद अभी भी किसी अलमारी में धूप सेंक रही हैं,और शहर पूछ रहा है-क्या अतिक्रमण हटाने की असली परीक्षा मुख्यमंत्री के जाने के बाद शुरू होगी, या फिर सब कुछ फिर से 'जैसा था वैसा' हो जाएगा?

पुलिस बल की कमी या इच्छाशक्ति की?

जनदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से यह तर्क दिया गया कि अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस बल उपलब्ध नहीं है। लेकिन यही शहर तब चौंक गया जब मुख्यमंत्री के आगमन की खबर मिलते ही उसी प्रशासन को अचानक पर्याप्त पुलिस बल भी मिल गया और बुलडोज़र भी, स्थानीय नागरिकों का सवाल सीधा है, क्या पुलिस बल भी वीआईपी कैलेंडर देखकर ही उपलब्ध होता है?

फल धूप में सूखते हैं या नियम?

नगर पालिका का तर्क है कि फल व्यवसायियों का माल धूप में खराब हो जाता है, इसलिए उन्हें दुकान के बाहर रखने की अनुमति दी गई है, लेकिन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अनुमति के नाम पर पूरी 12 फीट की गैलरी ही कब्जे में ले ली गई है। पैदल चलने के लिए छोड़ी गई जगह अब फल के क्रेट, तिरपाल और अस्थायी ढांचों से भरी पड़ी है, व्यंग्य करते हुए स्थानीय लोग कहते हैं कि बैकुंठपुर में अब नया नियम बन गया है-जहां धूप ज्यादा पड़े, वहां अतिक्रमण वैध।

आप भी बाहर निकाल लो-नियमों का नया सिद्धांत?

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि जब उन्होंने नगर पालिका से कार्रवाई की मांग की तो जवाब मिला-आप भी बाहर निकाल लो। यह कथन अपने आप में व्यवस्था की मानसिकता को उजागर करता है, अगर हर व्यक्ति को अतिक्रमण की खुली छूट दे दी जाए,तो फिर कानून की किताबों को संग्रहालय में रख देना ही बेहतर होगा।

सीएम का रास्ता और भाजपा कार्यालय के सामने सवाल

मुख्यमंत्री जिस मार्ग से गुजरेंगे, वहां भाजपा कार्यालय के सामने निर्माण सामग्री सड़क किनारे रखे जाने की चर्चा भी जोरों पर है। छोटे दुकानदारों के तिरपाल हटाने में जिस तेजी से कार्रवाई हुई,वही तेजी यहां क्यों नहीं दिख रही-यह सवाल शहर की चाय दुकानों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है,कुछ लोग तंज कसते हैं-बुलडोज़र भी शायद जीपीएस से चलता है,जहां आदेश मिले वहीं रुक जाता है।

सड़क चौड़ीकरण या चयनात्मक सफाई?

शहर में प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन पहले से तैयारी कर रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे ने इस तैयारी को अचानक मिशन मोड में बदल दिया,छोटे व्यवसायियों का दर्द यह है बता कि सालों से बैठकर रोजी-रोटी कमाने वाले लोगों को एक झटके में हटा दिया गया, जबकि प्रभावशाली जगहों पर बने अतिक्रमण पर फाइलों की धूल अभी भी मोटी होती जा रही है।

जनदर्शन पर उठता भरोसे का संकट

जनदर्शन को आम जनता की समस्याओं के समाधान का मंच बताया जाता है, लेकिन पुराने बस स्टैंड का मामला अब इस मंच की प्रभावशीलता पर सवाल बन गया है,कई बार शिकायत, कई बार खबर और कई बार आश्वासन-लेकिन परिणाम शून्य, लोग अब कहने लगे हैं कि जनदर्शन में समाधान कम और फोटो ज्यादा मिलते हैं।

पटना थाना में आरक्षक पर आरोपों की बौछार : मारपीट की शिकायत से खुले पुराने विवादों के पन्ने

मारपीट से अवैध कारोबार तक...पटना में जमे आरक्षक पर उठे बड़े सवाल,थाने के अंदर विवाद,बाहर चर्चाओं का बाजार-आरक्षक पर गंभीर आरोपों से पुलिस की साख दांव पर

शिकायत से गरमाया पटना थाना : लंबे समय से जमे आरक्षक पर कार्रवाई की मांग तेज,एक आरक्षक और कई आरोप...क्या सिस्टम की चुप्पी से बढ़ रहा विवाद?

स्थानांतरण के बावजूद लंबे समय से जमे रहने पर सवाल

पटना थाना क्षेत्र में आरक्षक के लंबे समय से पदस्थ रहने को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानांतरण आदेश की बातें सामने आने के बावजूद वह लंबे समय से इसी क्षेत्र में सक्रिय हैं। लोगों का मानना है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक जमे रहने से विवाद और शिकायतों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे पुलिस विभाग की छवि प्रभावित होती है,जानकारों का कहना है कि पुलिस विभाग में समय-समय पर स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शिता बनाए रखने और निष्पक्षता कायम रखने के लिए जरूरी मानी जाती है, ऐसे में यदि किसी कर्मी को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तो विभागीय स्तर पर गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए।

पुलिस की साख पर पड़ रहा असर

क्षेत्र के कुछ सामाजिक संगठनों और नागरिकों का कहना है कि लगातार सामने आ रहे आरोपों के कारण पूरे पुलिस महकमे की छवि प्रभावित हो रही है, उनका कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आम लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है,लोगों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो भी तथ्य सामने आएं,उसके आधार पर सख्त कार्रवाई हो,हालांकि कई लोगों का यह भी कहना है कि किसी भी पुलिसकर्मी पर लगाए गए आरोपों की जांच निष्पक्ष और तथ्यों के आधार पर ही होनी चाहिए,ताकि बिना पुष्टि के किसी की छवि को नुकसान न पहुंचे।

-रवि सिंह-

कोरिया/पटना,10 फरवरी 2026 (घटती-घटना)। जिले के पटना थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक अमल एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं, हाल ही में पुलिस अधीक्षक कोरिया सौंपे गए एक लिखित शिकायत पत्र में आरक्षक पर मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं, इस शिकायत के सामने आने के बाद क्षेत्र में पहले से चल रही चर्चाएं और पुराने आरोप भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं, जिससे पुलिस विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं,हालांकि,इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अधिकारियों की चुप्पी, जांच का इंतजार...

इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है,सूत्रों का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद विभागीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है, यदि जांच शुरू होती है तो मारपीट की शिकायत के साथ-साथ अन्य लगाए गए आरोपों की भी पड़ताल हो सकती है।

क्या कहते हैं जानकार

कानूनी जानकारों का कहना है कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ आने वाली शिकायतों की जांच बेहद संवेदनशील होती है,एक ओर जहां आम नागरिकों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना जरूरी है, वहीं दूसरी ओर बिना ठोस सबूत किसी पर आरोप तय करना भी उचित नहीं माना जाता,इसलिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही इस पूरे विवाद का सही समाधान मानी जा रही है।

मारपीट की शिकायत से शुरू हुआ नया विवाद

शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए आवेदन में बताया गया है कि 2 फरवरी 2026 को वह किसी मामले में थाना पटना में मौजूद था,इस दौरान आधार कार्ड मंगाने को लेकर हुई बातचीत के बीच कथित रूप से आरक्षक अमल कुमार ने बिना कारण गाली-गलौज शुरू कर दी और फिर मारपीट की,शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के दौरान थाना परिसर में अन्य लोग भी मौजूद थे,जिन्होंने पूरी घटना देखी और सुनी, पीड़ित ने जबड़े और कंपटी में चोट लगने की बात कहते हुए निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की है,शिकायतकर्ता का कहना है कि आरोपी आरक्षक उसी थाना में पदस्थ होने के कारण भय के माहौल में वह तत्काल रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सका। आवेदन पुलिस अधीक्षक को सौंपे जाने के बाद अब पूरे मामले पर विभागीय कार्रवाई को लेकर नजरें टिकी हुई हैं।

पुराने आरोपों की चर्चा फिर तेज

मारपीट की शिकायत सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कई लोगों ने आरक्षक के खिलाफ पुराने आरोपों को भी दोहराना शुरू कर दिया है, कुछ स्थानीय नागरिकों और सूत्रों का दावा है कि उक्त आरक्षक के खिलाफ पहले भी लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने और दबाव बनाने की शिकायतें आती रही हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है, सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि क्षेत्र में चल रहे कुछ कथित अवैध कारोबारों को संरक्षण मिलने की चर्चाएं समय-समय पर उठती रही हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने जुए के मामलों में भी आरक्षक का नाम सामने आने का दावा किया है, लेकिन इन सभी आरोपों पर अभी तक किसी आधिकारिक द्वारा पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए इन्हें जांच के दायरे में आने वाले आरोप ही माना जा रहा है।

CMYK

रणवीर सिंह को व्हॉट्सऐप पर मिली धमकी

धुरंधर एक्टर से की गई करोड़ों की डिमांड

सुपरस्टार रणवीर सिंह को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि व्हॉट्सऐप वॉइस नोट के जरिए धुरंधर एक्टर से करोड़ों की डिमांड की गई है।

सिनेमा जगत पर अंडरवर्ल्ड का साया एक फिर से मंडराता दिख रहा है। निर्देशक रोहित शेट्टी के बाद अब रणवीर सिंह को निशाना बनाया गया है। खबर है कि रणवीर को व्हॉट्सऐप वॉइस नोट के जरिए धमकी मिली है। धुरंधर अभिनेता से धमकी देने वाले ने करोड़ों रुपये की मांग की है। इस मामले की जानकारी मुंबई पुलिस द्वारा दी गई है। अनजान वॉइस-नोट सामने आने के बाद रणवीर सिंह घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अब मुंबई पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

रणवीर सिंह को मिली धमकी

कुछ दिन पहले हिंदी सिनेमा के लोकप्रिय निर्देशक रोहित शेट्टी की घर आधी रात पर फायरिंग हुई थी, जिससे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एक बार फिर से हिल गई थी। अब रणवीर सिंह को धमकी भरा वॉइस मिलने से हडकंप मच गया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अब किसी अनजान सोर्स से धमकी मिली है।

एक्टर को यह धमकी व्हॉट्सऐप वॉइस-नोट के रूप में मिली। मुंबई पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि धुरंधर फिल्म अभिनेता को जल्द से करोड़ों की धनराशि देनी होगी। इसके अलावा वॉइस नोट भेजने वाले सेंडर ने भी बताया है कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक रखता है।

रणवीर सिंह को धमकी मिलने के बाद अब मुंबई पुलिस एकदम अलर्ट मोड पर आ गई है और वॉइस नोट भेजने वाली की तलाश में जुट गई है। हालांकि,अभी मामले को लेकर रणवीर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। लेकिन सिनेमा जगत के सितारों को आए दिन इस तरह की धमकी मिलने से इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। मालूम हो कि रणवीर की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर बंपर तरीके कमाई करने में सफल रही है और इस वजह से उनका नाम भी चर्चा में बना हुआ है।

इन सेलेब्स को भी मिल चुकी है धमकी

ये पहला मौका नहीं है, जब किसी बॉलीवुड सेलेब्स को इस तरह से धमकी मिली है। इससे पहले सुपरस्टार शाह रुख खान और सलमान खान जैसे कलाकारों को कई बार धमकी मिल चुकी हैं। इतना ही नहीं सिंगर और रैपर हनी सिंह को भी इस तरह से धमकाया गया था।

42 नियमों की अग्निपरीक्षा पास करने के बाद ही मिलते हैं अल्लू अर्जुन?

अल्लू अर्जुन साउथ ही नहीं, बल्कि पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। उनकी फिल्म पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाया था। हालांकि,अब एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला ने दावा किया था कि उनसे मिलने से पहले 42 नियम आउटसाइडर्स को दिए जाते हैं। अब महिला के इस बयान पर अल्लू अर्जुन की टीम ने बयान जारी कर सच बताया है।

पुष्पा 2एक्टर अल्लू अर्जुन की एक बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी एक झलक पाने के लिए फैंस तरसते हैं। हालांकि,अब अल्लू अर्जुन को लेकर एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा था,जिसे देखकर फैंस भी हैरान हो गए थे।एक महिला ने साउथ सुपरस्टार्स और खासकर अल्लू अर्जुन से जुड़ा एक इंसिडेंट शेयर करते हुए बताया कि पुष्पा-2 एक्टर से मिलने से पहले उन्हें एक नोट मिलता है,जिस पर 42 रूल्स लिखे होते हैं। इस पर अल्लू अर्जुन की टीम ने रिएक्ट करते हुए जवाब दिया है।

अल्लू अर्जुन से मिलने से पहले मिलता है लंबा-चौड़ा नोट?

पैन इंडिया स्टार बन चुके अल्लू अर्जुन को लेकर एक महिला ने पॉडकास्ट में ये दावा किया था कि सुपरस्टार से मिलने से पहले 42 रूल्स बनाए गए हैं। ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम कर चुकी कावेरी बरुआ ने एक्टर और उनकी टीम को लेकर ये दावा किया था कि एक्टर से मिलने के कुछ प्रोटोकॉल हैं।

कावेरी का बयान था,हैदराबाद के मेगास्टार अल्लू अर्जुन से जुड़ा मेरा एक दिलचस्प इंसिडेंट है। साउथ के स्टार्स एक बड़ी टीम के साथ रहते हैं। उनसे मिलने से पहले,हमें एक 42 डूज और डोंट्स का नोट दिया गया था। उनके मैनेजर के मैनेजर के मैनेजर होते हैं। वह बहुत ही स्ट्रिक्ट थे,जैसे उनकी आंखों में मत देखना,उनसे हाथ मत मिलाना। इस वीडियो को अभिषेक नाम के एक फैन ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है।

वायरल वीडियो देखकर दो हिस्सों में बंटे फैंस

कावेरी बरुआ के ऐसा खुलासा करने के बाद जैसे ही इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि, उनकी आंखों में क्यों नहीं देख सकते हैं? तो कावेरी ने रिस्पांस करते हुए कहा, मेरे को क्या पता? यह रूल है। इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा और क्या-क्या रूल्स हैं? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, और नहीं बताऊंगी मैं।

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक यूजर ने लिखा, यह अल्लू अर्जुन के नहीं, बल्कि उनकी पत्नी के बनाए रूल्स हैं। दूसरे यूजर ने लिखा, कुछ भी, मेरे पिता जब विशाखापत्तनम में पुष्पा 2 की शूटिंग कर रहे थे,तो वह अल्लू अर्जुन से मिले थे। उनके साथ कोई बाउंसर और मैनेजर्स नहीं थे। आप सभी चीजें झूठ बोल रही हो। एक अन्य यूजर ने लिखा, अल्लू अर्जुन वहां का मोस्ट ओवररेटेड एक्टर है। वह बहुत ही घमंडी है।

अल्लू अर्जुन की टीम ने लगाई महिला को फटकार

इस पूरे मामले को लेकर हाल ही मे अल्लू अर्जुन की टीम ने महिला को फटकार लगाई है और इसके साथ ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंज भी जारी किया है। इस स्टेटमेंट के मुताबिक,महिला ने जो दावे उस पॉडकास्ट में पुष्पा स्टार को लेकर किए वो सरासर गलत हैं। इसके साथ ही अल्लू की टीम ने साफ किया है कि उस महिला के खिलाफ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा।

कभी रहीं टीवी की क्वीन,एक शो के लाखों रुपये करती थीं चार्ज,आज 1000 रुपये फीस लेकर चला रहीं घर

टीवी इंडस्ट्री में एक हसीना ने खूब नाम कमाया। 90 के दशक में टीवी पर उनका ही राज चला। एक-एक शो के लिए लाखों रुपये चार्ज करती थीं, लेकिन आज वह हजारों रुपये में गुजारा करने के लिए मजबूर हैं।

कभी ग्लैमर वर्ल्ड पर राज करने वालीं अदाकारा आज 1000 रुपये में गुजारा कर रही हैं। यह हसीना हैं 90 दशक की फेमस टीवी पर्सनैलिटी रूबी भाटिया ।रूबी भाटिया ने हिट फिल्मों में अदाकारी दिखाई और फिर टीवी होस्टिंग के जरिए खूब नाम कमाया। वह पहली वीडियो जॉकी थीं।

फिल्मों में अदाकारी के लिए वह टीवी शोज को होस्ट करती थीं। वह अपने दौर की हाइएस्ट पेड होस्ट्स में से एक थीं।

इंडस्ट्री से कर लिया था किनारा

90 के दशक में कामयाबी हासिल करने के बाद रूबी भाटिया ने अचानक इंडस्ट्री से किनारा कर लिया था। शादी के बाद वह अपने परिवार के साथ एक सिंपल लाइफ जी रही थीं कि तभी उन्हें अपना गुजारा करने के लिए 1000 रुपये फीस में काम करना शुरू किया।

इन दिनों रूबी भाटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है जिसमें वह 1000 रुपये फीस लेकर काम मांगती हुई नजर आई थीं। इस वीडियो को देख लोगों ने उनके फाइनेंशियल स्टेटस पर चिंता जताने लगे हैं। कभी एक शो के एक लाख रुपये कमाने वालीं रूबी का यूं 1000 हजार रुपये में काम मांगना लोगों के लिए शॉकिंग था।

रूबी भाटिया की खत्म हो गई थी सेविंग्स

कुछ समय पहले ही रूबी भाटिया ने बॉलीवुड ठिकाना को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था कि 20 सालों तक वह अपनी फैमिली के साथ एक शांत जिंदगी बिता रही थीं। वह अपने परिवार के साथ लोखंडवाला आती रहती थीं। जिस घर में वह रहती थीं, वह 30 साल पुराना था। जब उन्होंने उसे रेनोवेट करवाना शुरू किया तो बहुत खर्च हो गया और उनकी सारी सेविंग्स चली गई थी। डेली का 20 हजार रुपये रेनोवेशन में खर्च हो रहा था।

क्यों 1000 रुपये में काम कर रहीं रूबी भाटिया?

चोरी चोरी चुपके चुपके एक्ट्रेस रूबी भाटिया ने बताया कि उन्हें कमाना तो था ही लेकिन वह लंबे शूटिंग शेड्यूल में वापस जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा काम जो फोन पर भी किया जा सके। यहीं से उनके लाइफ कोच बनने की जर्नी शुरू हुई। उन्होंने 1000 रुपये में लाइफ कोचिंग शुरू की। रूबी इसलिए इतनी फीस लेती हैं, ताकि सेलेब्स के साथ-साथ आम लोग भी इसका लाभ उठा सकें।

9 करोड़ के कर्ज में डूबे राजपाल यादव के सपोर्ट में उतरा टीवी स्टार,फैंस बोले...क्राउड फंडिंग करते हैं...

9 करोड़ के चेक बाउंस केस में राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी इस मुश्किल घड़ी में अब एक-एक करके सितारे मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। सोनू सूद के बाद अब टीवी एक्टर ने भी अपनी क्षमता के अनुसार राजपाल यादव की मदद की बात कही जिसके बाद फैंस ने भी क्राउड फंडिंग करने का सुझाव दिया। पर्दे पर अपने अभिनय से सभी के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले राजपाल यादव की स्माइल कहीं खो गई है। इस वक्त कॉमेडियन एक्टर अकेले अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में फंसे राजपाल यादव इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। एक्टर की इस मुश्किल घड़ी में सोनू सूद ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया था। अब उनके बाद एक टीवी एक्टर भी राजपाल यादव के सपोर्ट में सामने आया है और इंडस्ट्री से उनकी मदद करने के लिए साथ आने की गुजारिश भी की है।

राजपाल यादव की हालत देख टीवी एक्टर का टूटा दिल

सोनू सूद के बाद अब छोटे पर्दे पर श्रीराम का किरदार निभाने वाले अभिनेता गुरमीत चौधरी ने राजपाल यादव की इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े होने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर मंगलवार को एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, सीनियर,बहुत ही टैलेंटेड एक्टर राजपाल यादव को इतने दर्द भरे दौर से गुजरते देखकर मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया है। वह हमेशा हमारे चेहरों पर अनगिनत स्माइल लेकर आए,हमें हंसाया और कई ऐसे यादगार पल दिए,जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। आज उन्हें हमारी जरूरत है।उन्होंने आगे लिखा, एक सह-कलाकार और इंसानियत के नाते,मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनकी मदद करूंगा। मैं निर्माता-निर्देशक और हमारी फिल्म फर्टेनिटी के मेंबर्स से भी ये गुजारिश करूंगा कि वह एक साथ आए और इंसानियत के नाते उनकी इस मुसीबत का सॉल्यूशन निकालें। हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है और फैमिली कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ती।

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने किया समर्थन भले ही आधी से ज्यादा इंडस्ट्री अभी इस मामले में शांत बैठी हो,लेकिन सोशल मीडिया पर गुरमीत चौधरी के इस एक्स पोस्ट पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं एक यूजर ने लिखा, यह बात सच में दिल में चुभ रही है कि वेटरन कॉमेडियन राजपाल यादव को लंबे समय से चल रहे उनके 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। फैमिली फ्रेंड्स कोई साथ नहीं है, इस बयान के बाद सोनू सूद और गुरमीत मदद के लिए आगे आए हैं। बॉलीवुड फैमिली, यही समय है साथ खड़े हो जाओ प्लीज।

दूसरे यूजर ने लिखा, सर हम सब मिलकर उनके लिए क्राउड फंडिंग कर लेते हैं। एक और अन्य यूजर ने लिखा,अच्छा लग रहा है ये देखकर फिल्म इंडस्ट्री में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं, जो लोगों की मदद के लिए सामने आते हैं।

शादी के 2 साल बाद ही दिव्या अग्रवाल पति से हो गईं अलग?

द 50 में नजर आ रहीं दिव्या अग्रवाल को लेकर को-कंटेस्टेंट भव्या सिंह ने एक बड़ा दावा कर दिया है जिसके बाद सनसनी फैल गई है। दिव्या ने अपूर्व पिलगांवकर से दो साल पहले शादी रचाई थी। दिव्या अग्रवाल एक बार अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं। द 50 में नजर आ रहीं भव्या सिंह ने दावा किया है कि दिव्या अपने पति अपूर्व पिलगांवकर से अलग रह रही हैं।

रियलिटी शो द 50 के लेटेस्ट एपिसोड में भव्या सिंह ने दिव्या अग्रवाल की निजी जिंदगी को लेकर ऐसा दावा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह सब शुरू हुआ, एक टास्क के दौरान।

दिव्या अग्रवाल की भव्या सिंह से हुई लड़ाई

दरअसल, द 50 के लेटेस्ट एपिसोड में दिव्या अग्रवाल को अर्चना गौतम और भव्या सिंह के साथ टास्क बैल एंड बुद्धि करना था। इसी टास्क के दौरान भव्या और दिव्या के बीच बहस शुरू हो गई है और बात यहां तक पहुंच गई कि भव्या ने बिग बॉस ओटीटी फेम दिव्या को गोल्ड डिगर बता दिया।

भव्या ने दिव्या को बताया गोल्ड डिगर

यही नहीं, भव्या सिंह ने सपना चौधरी समेत कुछ कंटेस्टेंट्स के साथ बात करते हुए दिव्या अग्रवाल की पर्सनल लाइफ के बारे में दावा किया कि वह अपने बिजनेसमैन पति अपूर्व पिलगांवकर से अलग रह रही हैं। उन्होंने दिव्या को फेक भी बताया।

पति से अलग रह रही हैं दिव्या?

इसके साथ ही भव्या सिंह ने कहा, दीवाली पर असली पटाखे तो इसके घर पर फूटे थे और मैंने फोड़े थे। आज तक मैंने कभी बोला नहीं वो। और ना कभी पॉडकास्ट पर कभी कुछ बोला, ना कभी बोलूंगी। क्योंकि इनका खुद का आपसी पारिवारिक मामला था। उसमें मुझे इन्वॉल्व कर दिया इन लोगों ने। भीख मांगते हैं लोगों से मुंबई में कि मेरे घर आ जाओ। प्लीज मिलो मुझसे। अलग रहती है अपने पति से।

खेल समाचार

वानिंदु हसरंगा टी 20 वर्ल्ड कप से बाहर

कोलंबो, 10 फरवरी 2026। अपने घर में हो रहे वर्ल्ड कप में मेज़बान श्रीलंका को एक और झटका लगा है। अपनी पहली जीत के साथ शानदार फॉर्म में चल रही टीम को वानिंदु हसरंगा की सर्विस नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह यह है कि सीनियर ऑलराउंडर चोट के कारण इस बड़े टूर्नामेंट से हट गए हैं। पहले मैच में आयरलैंड के खिलाफ तीन विकेट लेकर चमकने वाले हसरंगा को अचानक चोट लग गई। मेडिकल टेस्ट के बाद उन्हें आराम करने की सलाह दी गई। इसके साथ ही..यह मैच विनर उपलब्ध नहीं होगा। वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में कोई भी टीम अपने मुख्य खिलाड़ियों पर भरोसा करती है। लेकिन श्रीलंका ने इस बार वह मौका गंवा दिया है। पेसर इशान मलिंगा पहले ही चोट के कारण बाहर हो चुके हैं, और अब ऑलराउंडर हसरंगा भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं।

पूर्व जिम्नास्टिक कोच पर नाबालिगों को धमकाने का आरोप

रोम, 10 फरवरी 2026। इटली की रिदमिक जिम्नास्टिक टीम के पूर्व कोच पर मंगलवार को एथलीट्स को धमकाने का आरोप है। इससे देश में विंटर ओलंपिक्स की मेज़बानी के दौरान युवा एथलीट्स के साथ बर्ताव पर सवाल उठ रहे हैं। इमानुएला मैकरानी, जो खुद नेशनल टीम की पूर्व जिम्नास्ट रह चुकी हैं, पर मिलान के पास मोंज़ा की एक कोर्ट में नाबालिगों के साथ गलत व्यवहार के आरोप हैं, जो गेम्स का कुछ हिस्सा होस्ट कर रहा है। यह ट्रायल तीन साल पहले दो होनहार इटैलियन जिम्नास्ट, नीना कोराडिनी और दो बार की वर्ल्ड चैंपियन एना बास्टा के ज़बरदस्त दावों के बाद शुरू हुआ था। इन दोनों ने दावा किया था कि मैकरानी के साइकोलॉजिकल गलत व्यवहार की वजह से उन्होंने टीनएज में ही खेल छोड़ दिया था। कोराडिनी और बास्टा, दो अन्य जिम्नास्ट, बीट्राइस टॉर्नेटोर और फ्रांसेस्का मेयर, और चेंज द गेम, जो एक इटैलियन एसोसिएशन है जो स्पोर्ट्स में इमोशनल, फिजिकल और सेक्सुअल गलत व्यवहार और हिंसा के खिलाफ कैंपेन चलाती है, के साथ सिविल पार्टी हैं।

न्यूजीलैंड की लगातार दूसरी जीत

यूएई 10 विकेट से हारी
174 का टारगेट 15.2 ओवर में चेज, एलन-सइफर्ट में रिकॉर्ड साझेदारी

चेन्नई, 10 फरवरी 2026। न्यूजीलैंड टी-20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हासिल की है। कीवियों ने मंगवार के दूसरे मैच में यूएई को 10 विकेट से हराया। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर न्यूजीलैंड ने 174 रन का टारगेट 15.2 ओवर में बिना नुकसान के चेज कर लिया।

ओपनर टिम सइफर्ट (89* रन) और फिन एलन (84* रन) ने फिफ्टी लगाई। दोनों ने 175 रन ओपनिंग साझेदारी की। यह टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास में न्यूजीलैंड के ओपनर्स की सबसे बड़ी साझेदारी है।यूएई ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए। कप्तान मुहम्मद वसीम ने 66 रन बनाए। अलीशान शराफू ने 55 रनों का योगदान दिया।

हूं के मैट हेनरी ने 2 विकेट झटके। जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल सैंटनर और ग्लेन फिलिप्स को एक-एक विकेट मिला।

ग्रुप-डी के टॉप पर आया न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की टीम लगातार दूसरी जीत से ग्रुप डी की पॉइंट्स टेबल के टॉप पर आ गई है। टीम के पास 4 अंक हैं। टीम को कनाडा और साउथ अफ्रीका के साथ भी खेलना है। इस ग्रुप में साउथ अफ्रीका दूसरे स्थान के साथ दूसरे स्थान पर है।

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

यूएई:-अर्यांश शर्मा, मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मयंक कुमार, सोहैब खान, हर्षित कौशिक, मुहम्मद अरफान, ध्रुव पाराशर, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी और मोहम्मद राशिद खान।

न्यूजीलैंड:- टिम सइफर्ट, फिन एलन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चापमन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), जिमी नीशम, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन और जैकब डफी।

सचिन ने अंडर-19 डब्ल्यूसी जीतने वाले कप्तान को स्पेशल जर्सी गिफ्ट की

नई दिल्ली, 10 फरवरी 2026। अंडर-19 वर्ल्ड कप के हीरो की तारीफ़ हो रही है। दिग्गज खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बनकर घर लौटी भारतीय टीम को खास तौर पर बधाई दे रहे हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में कप्तान आयुष म्हात्रे को एक शानदार तोहफ़ा दिया। उन्होंने उन्हें भारत को बिना हारे लीड करने और उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए अपनी टेस्ट जर्सी दी। दिग्गज खिलाड़ी से कीमती तोहफ़ा पाकर मत्रे ने अपनी खुशी ज़ाहिर की।

टैलेंट को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहने वाले सचिन तेंदुलकर ने इस बार अंडर-19 वर्ल्डकप के कप्तान आयुष मत्रे को आसमान तक पहुंचा दिया। सचिन ने भारतीय टीम के लिए छठा कप जीतने पर उनकी तारीफ़ की.. और उन्हें एक यादगार तोहफ़ा दिया। मंगलवार को,क्रिकेट के दिग्गज ने मुंबई में अपने घर पर मत्रे को बधाई दी.. प्रिय आयुष.. और उन्हें एक टेस्ट जर्सी तोहफ़े में दी जिस पर लिखा था मैं तुम्हारे सफल करियर की कामना करता हूं। कड़ी मेहनत करते रहो। लोगों के कमेंट्स की परवाह मत करो। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं,प्रैक्टिस करना बंद मत करो। सचिन ने युवा क्रिकेटर को कीमती सलाह देते हुए कहा कि तुम्हें खेल पर ध्यान देना चाहिए।

बचपन से सचिन को खेलते हुए देखकर बड़े हुए आयुष उनसे कीमती तोहफ़ा पाकर बहुत खुश हैं। उन्होंने अपनी खुशी शेयर की। मैं बचपन से आपको टीवी स्क्रीन पर देखते हुए बड़ा हुआ हूं। आज मैं आपके घर में हूं। एक शानदार तोहफ़ा जो आपकी क्रिकेट यात्रा का हिस्सा है, अब मेरे हाथों में है। मुझे यह सम्मान देने के लिए धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने सालों तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की है, मैं आपका सम्मान करता रहूंगा, मात्रे ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कहा।

एल्विस स्माइली ने रियाद में जीती एलआईव्ही गोल्फ

रियाध, 10 फरवरी 2026। एलआईव्ही गोल्फ रियाद 2026 के साथ, 22 साल के ऑस्ट्रेलियाई एल्विस स्माइली की सफलता ने–जिन्होंने पिछले वीकेंड रियाद गोल्फ क्लब में जीत हासिल की–लीडरबोर्ड पर सिर्फ प्रोफेशनल्स को ही नहीं,बल्कि और भी लोगों को प्रेरित किया है।

एलआईव्ही गोल्फ रियाद 2026 का टाइटल पार्टनर आरओएसएचएन ग्रूप, अब आर ओ एस एच एन राइजिंग स्टार्स प्रोग्राम को बढ़ाकर उस मोमेंटम को और बढ़ाना चाहता है। यह एक ऐसी पहल है जिसे सऊदी के युवा गोल्फरों की अगली पीढ़ी के लिए मौके बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूके और यूएस में एलआईव्ही गोल्फ इवेंट्स में महीनों की ट्रेनिंग और एक्सपोजर के बाद, जिसमें रियाद प्रो-एम टूर्नामेंट में हिस्सा लेना भी शामिल है, यह प्रोग्राम अपने अगले फेज में जाने के लिए तैयार है, जो पूरे किंगडम में कुल 100 उभरते हुए गोल्फरों को सपोर्ट करने के लिए बढ़ाया जाएगा। अरब न्यूज़ ने आरओएसएचएन ग्रूप में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर टायलर जैकबसन से प्रोग्राम की ग्रोथ और इसके लॉन्ग-टर्म विजन के बारे में बात की।

CMYK

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 6412 जोड़ों का सामूहिक विवाह...

राजधानी में सीएम साय की मौजूदगी में 1316 जोड़ों ने लिए सात फेरे,गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ आयोजन

रायपुर,10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में आज एक ऐतिहासिक दिन दर्ज हो गया,जब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रदेशभर में एक ही दिन में 6,412 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। इसका मुख्य कार्यक्रम रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित किया गया,जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में 1,316 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय,महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े,मंत्री गुरु खुशवंत साहेब,विधायक और निगम मंडल के अध्यक्ष शामिल हुए। सभी जनप्रतिनिधि पारंपरिक साफा बांधकर बाराती की भूमिका में नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री ने मंच से नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक विवाहित जोड़े के खाते में 35 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है,जबकि 15 हजार रुपये उपहार सामग्री और विवाह आयोजन पर खर्च किए गए हैं। बलौदाबाजार,धमतरी,दुर्ग,महासमुंद और राजनांदगांव जिलों के जोड़े ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े।

विभिन्न समाजों के जोड़े,आत्मसमर्पित नक्सलियों का भी विवाह

प्रदेश में हुए विवाहों में 6,281 हिंदू रीति,10 बैगा जनजाति,3 मुस्लिम,5 बौद्ध और 13 ईसाई समाज के जोड़े शामिल रहे। खास बात यह रही कि 6 आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों के विवाह भी सामूहिक आयोजन में कराए गए। गरियाबंद में 4,जबकि सुकमा और दंतेवाड़ा में एक-एक जोड़े का विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के आत्मसमर्पित नक्सली दंपति से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर उन्हें दांपत्य जीवन की शुभकामनाएं दीं।

कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ भी किया। पहले चरण में 6 माह से 52 माह तक के 40 हजार कुपोषित बच्चों को शामिल किया जाएगा। अभियान की शुरुआत बस्तर संभाग के बीजापुर,दंतेवाड़ा,नारायणपुर और सुकमा जिलों से होगी। कार्यक्रम में मंच से महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने मजाकिया अंदाज में कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत इसी स्थल पर युवा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब का विवाह कराने की भी इच्छा थी, लेकिन उन्हें कन्या नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगली बार जब कन्या विवाह का आयोजन होगा, तब गुरु खुशवंत साहेब का विवाह भी कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय का संबोधन

वहीं मुख्यमंत्री साय ने अपने संबोधन में कहा कि नया जीवन शुरू करने वाले बेटी-दामाद को शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज 6 हजार 412 जोड़ों ने अपना नया जीवन शुरू किया। उनका दांपत्य जीवन सुखमय और मंगलमय हो। यह योजना वर्ष 2005 में डॉ. रमन सिंह के कार्यकाल में शुरू की गई थी। पहले बेटी की शादी को लेकर परिवारों को चिंता रहती थी। आर्थिक समस्याएं होती थीं, पिता को कर्ज लेना पड़ता था और बेटी की शादी के कई साल बाद तक कर्ज चुकाना पड़ता था। डॉ. रमन सिंह बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस योजना की शुरुआत की। यह एक बहुत अच्छी योजना है। अलग-अलग शादी होती तो इतने लोग एक साथ आशीर्वाद देने नहीं पहुंच पाते। हमारी सरकार को अब दो साल पूरे हो गए हैं। प्रदेश में एक ही दिन में 6 हजार 412 जोड़ों के विवाह के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह समारोह में एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। रायपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर कुल 6 हजार 412 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है।

छत्तीसगढ़ में एसआईआर की प्रक्रिया में आई तेजी...98% नोटिसों की सुनवाई पूरी

रायपुर,10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची को शुद्ध, पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 की प्रक्रिया तीव्र गति से संचालित की जा रही है। एसआईआर के अंतर्गत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 23 दिसंबर 2025 को किया गया था। इसके बाद दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक पूरी की गई। वर्तमान में प्राप्त दावों एवं आपत्तियों पर सुनवाई और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी है। एसआईआर की गणना चरण के दौरान प्राप्त गणना प्रपत्रों के आधार पर जिन मतदाताओं का मिलान वर्ष 2003 की विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची से नहीं हो पाया,उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए गए। सभी संबंधित मतदाताओं को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य 13 निर्धारित दस्तावेजों में से आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। नियमानुसार सुनवाई एवं दस्तावेजों के परीक्षण के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किए जाने अथवा न किए जाने का अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। यह प्रक्रिया 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेगी। अब तक राज्यभर में जारी किए गए लगभग 98 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूरी की जा चुकी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद दावा-आपत्ति अवधि के दौरान जिन वैध मतदाताओं का नाम सूची

में शामिल नहीं था,उन्होंने नाम जोड़ने के लिए प्रपत्र-6, मतदाता विवरण में सुधार के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-8 एवं नाम विलोपन अथवा आपत्ति के लिए घोषणा पत्र सहित प्रपत्र-7 प्रस्तुत किए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दावा-आपत्ति अवधि (23 दिसंबर 2025 से 22 जनवरी 2026) के दौरान विधानसभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा साप्ताहिक बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों में प्रति सप्ताह प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई, ताकि राजनीतिक दलों द्वारा सूचियों का अवलोकन कर पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने एवं अपात्र मतदाताओं के नाम विलोपन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके। दावों एवं आपत्तियों की सुनवाई तथा सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पात्र पाए गए आवेदनों का विधिवत निस्तारण किया जा रहा है। 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

सीएम हाउस का घेराव करने निकली आम आदमी पार्टी को पुलिस ने रोका

नेता बोले...किसानों को एक मुश्त राशि मिले एक-एक दाना खरीदकर वादा पूरा करे सरकार

रायपुर,10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर आम आदमी पार्टी मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकली थी, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। पार्टी का कहना है कि राज्य में लाखों किसान अब भी धान बेचने से वंचित हैं,इसलिए धान खरीदी की अंतिम तारीख 28 फरवरी तक बढ़ाई जाए। किसानों का एक-एक दाना खरीदे सरकार और अपना वादा पूरा करें। आप नेताओं का आरोप है कि धान का भुगतान लेने के लिए किसान सहकारी बैंकों में सुबह 6 बजे से देर रात तक कड़ी धूप में लाइन लगाने को मजबूर हैं। इसके बावजूद बैंकों से एक बार में सिर्फ 25 हजार रुपए ही भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसानों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसलिए एक मुश्त राशि दी जाए।

सरकार पर रकबा समर्पण का दबाव बनाने का आरोप

पार्टी ने आरोप लगाया कि,सरकार ने साजिश के तहत लाखों छोटे किसानों से जबरन रकबा समर्पण करवाया। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब 3 लाख किसान अब भी धान बेच नहीं पाए हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार की नीयत शुरू से ही धान खरीदी की नहीं थी, इसलिए लगातार नए बहाने बनाए गए।

खरीदी केंद्रों की लिमिट कम,किसान परेशान

आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार धान खरीदी केंद्रों की प्रतिदिन की लिमिट कम कर दी गई,जिससे किसान सिर्फ टोकन लेकर लाइन में खड़े रहने को मजबूर हुए। टोकन जारी करने से पहले पटवारी, आरआई और तहसीलदारों की ओर से किसानों के घर जाकर भौतिक सत्यापन भी कराया गया। पार्टी ने सवाल उठाया कि क्या सरकार किसानों को संदेह की नजर से देख रही है?

केंद्र की ट्रेड डील पर भी सवाल

आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की अमेरिका के साथ नई ट्रेड डील को भी किसान विरोधी बताया। पार्टी का कहना है कि इस समझौते से अमेरिका के कृषि और डेयरी उत्पाद सस्ते दामों पर भारत में आएंगे, जिससे देश की कृषि व्यवस्था और किसानों को बड़ा नुकसान होगा।

कर्ज में डूबे किसान सरकार जिम्मेदार

पार्टी का दावा है कि प्रदेश में करीब 3 लाख किसान अब भी धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में जिन किसानों ने कर्ज लिया है, वे गंभीर आर्थिक संकट में हैं। आम आदमी पार्टी ने धान खरीदी में अव्यवस्था के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।

28 फरवरी तक तारीख बढ़ाने की मांग

आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि जबरन रकबा समर्पण करवाने के मामले में सरकार किसानों से माफी मांगे, सभी किसानों के लिए बेहतर टोकन व्यवस्था लागू करे और जरूरत पड़ने पर सहकारी समितियों के जरिए सीधे धान खरीदी कराई जाए। पार्टी ने 6 फरवरी को खत्म हुई धान खरीदी की समय-सीमा को 28 फरवरी तक बढ़ाने की मांग दोहराते हुए कहा है कि किसानों की मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

हाई कोर्ट ने निरस्त की व्याख्याता के रिटायरमेंट के बाद जीपीएफ से वसूली,कहा- 6 माह बाद किसी भी किस्म की वसूली अवैध

बिलासपुर,10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में व्याख्याता के रिटायरमेंट के 6 माह बाद जीपीएफ से वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सेवानिवृत्त होने के 6 माह बाद किसी भी शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) की राशि से किसी भी प्रकार की वसूली करने को अवैध माना जाएगा। जांजगीर-चांपा जिले के पामगढ़ निवासी सेवानिवृत्त व्याख्याता लक्ष्मी नारायण तिवारी ने याचिका दाखिल की थी। वे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय,ससहा में व्याख्याता के पद पर पदस्थ थे। लक्ष्मीनारायण तिवारी 31 जनवरी 2011 को 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर रिटायरमेंट हुए थे। रिटायरमेंट के करीब 12 साल बाद महालेखाकार कार्यालय रायपुर ने उनके जीपीएफ खाते में ऋणात्मक शेष दर्शाते हुए उनके खिलाफ वसूली आदेश जारी कर दिया। इस आदेश से क्षुब्ध होकर लक्ष्मीनारायण तिवारी ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि शासकीय कर्मचारी के रिटायरमेंट के 6 माह के अंदर ही देयकों की वसूली की जा सकती है। इसके बाद वसूली करना नियमों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 के नियम 65 का हवाला देते हुए बताया गया कि यदि किसी शासकीय सेवक के जीपीएफ खाते में ऋणात्मतक शेष पाया जाता है।

ज्ञान,तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में विशेष पहचान बनाएगा छत्तीसगढ़ : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,10 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध राज्य है। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ ज्ञान,तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भी देश में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए। छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को ज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है।आधुनिक अधोसंरचना,प्रभावी ई-गवर्नेंस प्रणाली और निवेश-अनुकूल नीतियों के चलते छत्तीसगढ़ आज आईटी, आईटीईएस एवं इमरजिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों के लिए एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज अपने निवास कार्यालय में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना

प्रौद्योगिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन एवं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एस टी पी आई) के मध्य हुए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) उपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि युवाओं में उद्यमिता विकसित करने और उन्हें आईटी एवं आईटीईएस जैसे क्षेत्रों में विश्वस्तरीय अवसर राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल की गई है। इस एमओयू के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एवं इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वन एवं औषधीय उत्पाद आधारित मेडटेक,स्मार्ट सिटी समाधान तथा स्मार्ट कृषि जैसे चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नवाचार और स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी,जो प्रति वर्ष लगभग 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप और एमएसएमई को प्रोडक्ट डिजाइन,प्रोटोटाइपिंग, कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण की सुविधाएं प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस पहल से प्रदेश के युवाओं को राज्य के भीतर ही इनक्यूबेशन, मेंटरशिप, फंडिंग और आधुनिक प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध होगी।

शिवरीनारायण मेले में बड़ा हादसा..आकाश झूला टूटने से 6 लोग गिरे,2 युवतियों की हालत नाजुक,महिला समेत 3 अन्य घायल

जांजगीर-चांपा,10 फरवरी 2026। शिवरीनारायण मेला में आज बड़ा हादसा हो गया। मेले में लगे आकाश झूले के अचानक टूट जाने से झूले पर सवार 6 लोग नीचे गिर पड़े,जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में 2 युवतियां और 1 महिला जमीन पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गईं,जबकि 3 अन्य लोगों को भी चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल दोनों युवतियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन की मदद से एंबुलेंस बुलाकर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार,घायल युवतियां मलदा गांव की रहने वाली हैं,जो मेला घूमने शिवरीनारायण आई थी। घायलों की पहचान चंद्रकांता कश्यप और भूमिका कश्यप के रूप में हुई है।

आईएएस अंकित को सीआरडीए के सीईओ का मिला अतिरिक्त प्रभार

रायपुर,10 फरवरी 2026। । छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वर्ष 2006 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी अंकित आनंद को छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (सीआरडीए) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। अंकित आनंद वर्तमान में राज्य शासन में कई महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वे सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पदस्थ हैं। इसके साथ ही उन्हें अतिरिक्त प्रभार के रूप में सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सचिव, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग की

जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इसके अलावा वे अध्यक्ष,छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के रूप में भी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य शासन ने उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव और कार्यक्षमता को देखते हुए उन्हें सीआरडीए के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण राजधानी रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के सुनियोजित विकास, आधारभूत संरचनाओं के विस्तार, आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रशासनिक हलकों में इस निर्णय को राजधानी क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अंकित आनंद के पास शहरी विकास, पर्यावरण संरक्षण और आईटी से जुड़े विभागों का अनुभव होने के कारण सीआरडीए की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

भूपेश बघेल सहित 3 कांग्रेस नेताओं पर 500 करोड़ का मानहानि केस दर्ज

रायपुर, 10 फरवरी 2026। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह, भूपेश बघेल और गौरव गोगोई के खिलाफ मानहानि का केस किया है, जिसमें 500 करोड़ के हर्जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तीनों नेताओं ने जानबूझकर उनके खिलाफ झूठे, गलत इरादे वाले और बदनाम करने वाले आरोप लगाए। गौरतलब है कि 4 फरवरी को असम कांग्रेस के प्रेसिडेंट गौरव

गोगोई ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के परिवार ने राज्य में करीब 12,000 बीघा ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से कब्ज़ा कर लिया है, जो 3,960 एकड़ से ज़्यादा एरिया में फैला है। मुख्यमंत्री सरमा को हाल ही में धार्मिक भेदभाव को लेकर दिए गए अपने बयानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों और सिविल सोसाइटी के अलग-अलग तबकों की आलोचना का सामना करना पड़ा है। इस बैकग्राउंड में, ज़मीन से जुड़े आरोप सामने आने के बाद यह मुद्दा और भी गरमा गया है। इन आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री ने साफ़ किया है कि वे गौरव गोगोई समेत कांग्रेस नेताओं के खिलाफ़ कानूनी मानहानि का केस चलाएंगे। इस बीच, गोगोई ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री के इस कदम को घबराहट का संकेत बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि अगर मुख्यमंत्री में हिम्मत है, तो उन्हें शरण लेने के बजाय कोर्ट में खुलकर लोगों का सामना करना चाहिए।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह*(पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)